[Shri P.Chetia]

the various banks at the instance of their directors, came to Rs. 228 crores. Such loans and advances to various firms and companies increased to Rs. 378 crores in 1967. This shows how far and to what extent the resources of the banks are being utilised for the benefit of a few, which ultimately results in concentration of economic power and wealth in the hands of a few, thus leading to a monopolistic system in the society to the detriment of the larger interests of the people. The present Bill seeks to do away with this bane.

I welcome the creation of the National Credit Council which would look into the credit facilities now prevalent and devise ways and means to extend such credit facilities to all sections of the people who arc found to be legitimately entitled to such facilities.

I also welcome the creation of a Banking Commission as mentioned by the Finance Minister in his speech. It is indeed a very welcome proposal and the Commission should go in detail into the structure, procedure and working of the banking system in the country and suggest remedies which are found essential in the interest of the common wealth. In this connection I would like to suggest that the rural credit system should be thoroughly enquired i nto and organised properly. Our cultivators in the countryside are heavily indebted to the village money- enders who charge very exorbitant rates of interest, to the extent of 100 per cent sometimes. In this connection, I would like to refer to the State of Assam where there are a few hundreds of "Kabulis", who are Afghan nationals and who do money lending business both in the towns and in the villages at the fabulous interest rate of 150 to 300 per cent. I would like to suggest that such nefarious activities of the moneylenders should be curbed and they should not be allowed to carry on such business in this country.

With these words, I support the motion.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

2 P.M.

The House reassembled after lunch at two of the clock. THE VICE-CHAIRMAN [SHRI M. P. BHARGAVA] in the Chair.

MOTION *RE* THE DROUGH1 SITUATION EM THE COUNTRY

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE) : Sir, on behalf of Shri Jagjivan Ram I beg to move—

"That the situation arising out of the drought conditions prevailing in parts of the country be taken into consideration."

Sir, in regard to this we have already laid a statement on the Table of the Rajya Sabha. Therefore, I Would not like to make any observations at this stage. It would be better if Members make their observations first. Then, it would be possible for me to reply at the end. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA) : There are three amendments. One is in the name of Shrimati Mangladevi Talwar. She is not here. The other two amendments are by Shri Banka Behary Das. Mr. Das, are you moving your amendments?

SHRI BANKA BEHARY DAS (Orissa): Sir, I beg to move—

(1) "That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

'and having considered the same this House is of opinion that (i) the Central Government should render full assistance for relief and rehabilitation of the people affected according to reasonable demands of the States; (ii) the Central Government should immediately set up a cell in the de-department concerned or the Planning Commission to evolve a programme of utilisation of all water potential, both surface and underground, to fight di ought and augment production; (iii) the draft of the Fourth Five Year Plan should be revised accordingly to give priority to utilisation of water potential to the maximum extent; and (iv) the Government of India should set up an all-India fund for relief and rehabilitation of people affected by flood and drought or any other natural calamity.' "

(a) "That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :—

'and having considered the same, this House regrets that the statement of the Minister on "drought conditions prevailing in parts of the country ', laid on the Table of the Rajya Sabha on November 18, 1968, does not mention anything about starvation deaths of Rajasthan, nor about death of thousands of cattle which are emaciated due to want of fodder or drinking water'."

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Now, the motion and the amendments are before the House. I might tell the hon. Members in the beginning that there are several names and that we shall be debating up to 5.30. At 5.30 the Minister will be asked to reply. I would request the honourable Members to limit their remarks to 15 minutes so that as many of the hon. Members as possible may be accommodated.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न के बारे में समय का निर्धारण अभी न करें, डिबेट को प्रारम्भ होने दें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : मैं तो बटवारा कर रहा हूं निर्धारण नहीं कर रहा हूं ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: क्योंकि यह देशव्यापी है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : आप शुरू कर रहे हैं ? आप शुरू कीजिए ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : लेकिन मैंने जो निवेदन किया है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : वह ठीक है । आपको मैं 2-20 पर बताऊंगा ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उपसभाध्यक्ष महोदय, जब पिछला राज्य सभा का सत्र चल रहा था उस समय देश के अन्दर आने वाले भीषण अकाल की स्थिति के बारे में इस सदन में चर्चा हुई थी । उस समय भी विभिन्न सदस्यों ने, जो संकट आ रहा है और जिस भीषणता से आ रहा है उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया था क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यह संकट विशेषकर देश के कुछ हिस्सों में, लगातार कुछ वर्षों से चला आ रहा है । दुख इसी बात का है कि प्रति वर्ष यहां इसका उल्लेख होता है, प्रति वर्ष उसके बारे में कुछ दीर्घ-कालीन कदम उठाने की बात भी कही जाती है, परन्तु आने वाले वर्ष में यह संकट और बढ़ता हुआ, अधिक खतरा धारण करता हुआ दिखाई देता है । राजस्थान का मैं यहां उल्लेख विशेष रूप से करना चाहूंगा । जैसा मैंने पहले भी कहा है, राजस्थान के कुछ भागों में यह अकाल का पांचवां वर्ष है, कुछ भागों में यह सातवां वर्ष है । पिछले दिनों में धीरे-धीरे यह संकट बढ़ा है । अभी तो हम सर्दी की शुरूआत में हैं । पता नहीं अगली वर्षा ऋतु तक यह संकट और कितनी भीषणता ग्रहण करेगा ।

यहां पर जो स्टेटमेंट रखा गया है—18 नवम्बर को रखा गया था— उसमें राजस्थान के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि 3,377 गांव, और 24 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं, यह आंकड़ा दिया गया है । मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि 18 नवम्बर तक का भी यह आंकड़ा सही है या नहीं इसको वह जरा दुबारा देख लें क्योंकि राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति में 15 नवम्बर के पहले भी 7,584 गांव अकाल-ग्रस्त घोषित किए जा चुके थे और उसके बाद भी 13,558 गांव अकालग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं । राजस्थान के मुख्य मंत्री अभी पिछली 29 तारीख को कलकत्ते में थे । उन्होंने वहां पर यह घोषणा की कि राजस्थान में 26 हजार गांव और डेढ़ करोड़ जनसंख्या अकाल से प्रभावित है और करीब 60 से 70 लाख पशु अकाल से प्रभावित हैं । मैं यह समझता हूं कि यहां का खाद्य मंत्रालय अगर इस सारे आंकड़ों को आज की सही स्थिति के आधार पर एक बार स्वीकार कर लेगा तो उसको कदम उठाने में भी, उसके लिए आवश्यक प्रबन्ध करने म

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

भी सहूलियत होगी। मेरा निवेदन यह है कि यहां पर शायद इस समस्या की विकटता को--जो स्टेटमेंट यहां पर रखा गया है उसके अनुसार---जितनी गम्भीरता से लेना चाहिए या जितना इसका व्यापक परिणाम आज वहां पर हो रहा है उसके सन्दर्भ में अभी तक देखा नहीं गया है। मैं चाहता हूं कि उस सन्दर्भ में इसको देखा जाय।

वह काफी लम्बे समय स यह समस्या चली आ रही है। इसलिए स्वाभाविक है कि वहां पर मवेशियों के लिये घास का अभाव है, वहां पर जल का अभाव है, खेती नहीं है और लोगों के पीने तक के लिए पानी नहीं है। जब से यह समस्या खड़ी हुई है तब से आज तक इस प्रभावित क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में मवेशियों को हटा लेना पड़ा है, जनसंख्या को भी वह क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बहुत से मवेशी हटाते समय, अन्य क्षेत्रों में भेजते समय इतने दुर्बल हो गए थे कि उनके लिए चल कर जाना असम्भव हो गया लाखों मवेशी इस कारण वहां पर मरे हैं।

वहां पर अकाल से पीड़ित मनुष्यों की मौत के बारे में विवाद चल रहा है। और बार-बार सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन इसके सम्बन्ध में वक्तव्य आए हैं। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा बीकानेर के भूतपूर्व मेडीकल आफीसर डा० असोपा का, उन्होंने 24 लोगों के नाम दिए हैं कि इन लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है। उसके बारे में अभी तक कोई डेफिनिट सरकार की तरफ से कुछ नहीं निकला कि यह झूठी खबर है या गलत खबर है। इसी प्रकार से बाड़मेर की शिव तहसील में 9 नवम्बर से 17 नवम्बर के बीच में 35 लोगों की मृत्यु का समाचार है जिसके बारे में भी कोई स्पष्ट खंडन नहीं हुआ है। मेरा यह निवेदन है कि इन आंकड़ों के बारे में कि वह 35 है यह 25 है, 5 या 10 है, यह विवाद हो सकता है लेकिन यह समस्या इतनी एक्यूट बनी हुई है इसको हम स्वीकार करें।

मैंने यह उस समय भी कहा था कि वहां के लोगों को माइलो खाने को दिया जा रहा है। कहा गया कि यह ठीक है, वह खराब नहीं। मैं समझता हूं कि भूखे लोगों को केवल माइलो की खूराक अपौष्टिक है और आज इस कारण से उन लोगों में से 50 फीसदी लोगों को रतौंधी की बीमारी हुई है, अंधेरा पड़ने के बाद उनको दिखता नही इसकी रिपोर्ट आई और जैसे ही अधिकारियों को इस बात की सचाई का अनुभव हुआ एकदम से उन्होंने सारा माइलो विदड्रा करके कुछ जगहों पर गेहूं भेजने की की कोशिश की। गेहूं का भाव बहुत महंगा है, उनकी मजदूरी पूरी नही पिछले दिनों में गेहूं का भाव 78 रुपए क्विन्टल से बढ़ा कर 99 रुपए क्विन्टल कर दिया गया। अकालग्रत क्षेत्र में 21 रुपए क्विन्टल की भाव में बढ़ोत्तरी। ऐसे समय में इतना महंगा गेहूं वहां लोग खरीद नहीं सकते। वहां के लोगों का साधारण भोजन बाजरा है। पिछले दिनों में भी सरकार के गोदामों में बाजरा आया है, पिछले साल भी वसूली हुई। जिस खाने से उनकी भूख को शमन किया जा सकता है और जो उनके खरीदने की ताकत में है पता नहीं क्यों सरकार उसको उपलब्ध नहीं कर रही है ?

दूसरा प्रश्न है वहां मजदूरी प्राप्त होने का और बहुत जगहों पर बिलकुल अधिकृत रूप से सूचना मिली है कि बीस बीस दिन या इक्कीस इक्कीस दिन तक लोगों को मजदूरी नहीं मिली, यह कायदे के अन्दर होते हुये भी कि सात दिन में मजदूरी मिल जानी चाहिये। वहां पर गडरा रोड में, 10 नवम्बर की रिपोर्ट है कि काफी दिनों तक मजदूरी नहीं मिली, कोलायत में 1 नवम्बर से 23 नवम्बर पक मजदूरी नहीं मिली और और भी जगह से इस बात की शिकायत है कि मजदूरी नहीं मिलती। वहां के मस्टर रोल में क्या गड़बड़ी है, मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, शायद यहां बैठा मंत्रालय उसके बारे में सीधे कुछ हिसाब देख सके इसके लिये

आशा करना बहुत दूर की बात होगी लेकिन इतना जरूर है कि ये जितने भी राहत के कार्य चल रहे हैं---इसकी मंत्री महोदय को भी जानकारी होगी---वहां बीस बीस मील और तीस तीस मील दूर से लोग चल कर के इन राहत के कामों पर आ रहे हैं। अब वहां यह रेगिस्तानी इलाका है और यहां भी दिल्ली में मंत्रिमंडल के कोई सदस्य यदि पांच बजे सुबह घूमने निकलते होंगे तो उनको सर्दी का थोड़ा अंदाजा होता होगा और वहां तो सर्दी की भीषणता अधिक है और बीस बीस मील से काम पर आने वाले लोग जो कि पहले ही अपौष्टिक भोजन के शिकार हैं उनके लिये जहां राहत कार्य चल रहे हैं वहां किसी तरह के शेल्टर की या झोंपड़ी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर लोग झाड़ियों के नीचे---पेड़ की उसको संज्ञा नहीं दी जा सकती---वह झाड़ियों के नीचे रात भर सिकुड़ते हुये जो थोड़ा बहुत तिनका इधर उधर सूखा मिल जाय उन्हीं को चुन कर और जला कर किसी तर गुजारा करते हैं। कम भोजन, अपौष्टिक भोजन और भीषण सर्दी, इनके कारण एक बहुत बड़ी विपदा इस समय वहां की सारी जनसंख्या पर उपस्थित है, इसलिये यह आवश्यक है कि इन सारी चीजों के संदर्भ में इसका विचार किया जाय। वहां पर जो राशन शाप्स हैं वह भी जहां जहां रिलीफ वर्क्स खोल दिये गये हैं वहां वहां नहीं हैं और दूर दूर से लोग किसी तरह राशन शाप्स पर जाते हैं तो लोगों को कह दिया जाता है कि आज जितना अनाज हमें देना चाहिये था वह तो खत्म हो गया। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। बाड़मेर की तरफ रेलवे स्टेशन बीस बीस मील दूर है वहां लोग राशन-शाप्स पर अनाज लेने आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि फिर आना, आज का अनाज खत्म हो गया है और उन्हें लौट कर जाना पड़ता है। तो इन राशन शाप्स की संख्या बढ़ा कर जहां पर भी जनसंख्या बैठी है वहां तक उनको ले जाने का आप प्रबन्ध करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

वहां पर सभी पार्टियों की मिल कर के अकाल के निवारण के लिये एक कमेटी बनी। मैं समझता हूं कि अकाल कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है और इसी आधार पर इसका विचार करना चाहिये लेकिन हम इस बात को ध्यान में रखें कि पहले भी इस अकाल के ऊपर बहुत पैसा खर्च हुआ है। सन् 1966-67 में 13 करोड़ 34 लाख रुपया राजस्थान में अकाल पर खर्च हुआ और 1967-68 में 7 करोड़ 75 लाख रुपया राजस्थान के बजट में इसके लिये रखा गया, एक्चुअल्स की फिगर्स अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, तो दो वर्षों में 21 करोड़ रुपया अकाल के ऊपर खर्च किया जा चुका है और पिछले आठ-दस वर्षों में 50 या 60 करोड़ रुपया राजस्थान में अकाल के निमित्त खर्च हुआ है। अब इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, प्रति वर्ष खर्च कर रहे हैं और अकाल की भीषणता बढ़ती जा रही है, इसका हमें विचार करना चाहिये कि इन सारी चीजों का खर्चा किस प्रकार हो रहा है, खर्च हम ठीक जगह पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अकाल के एक स्थायी निवारण के लिये कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं। इसके सम्बन्ध में केन्द्र की तरफ से भी इस चीज की कोई न कोई निगरानी की जाय, केवल कहने से या रुपया एलाट करने से काम नहीं चलेगा।

आपने उस दिन उल्लेख किया, जांच करने के लिये एक कमेटी गई थी लेकिन अजीब बात है कि वह जांच करने वाली कमेटी भी इस सारे क्षेत्र में नहीं गई, वह भी कुछ चुनिन्दा जगहों पर गई। मंत्री जी नहीं जा सके, प्रधान मंत्री जी नहीं जा सकीं, उन्होंने कहा कि हर जगह नहीं जा सकते, खैर उनको फुर्सत नहीं है तो न जांय, मगर जो जांच करने के लिये कमेटी गई वह भी उनमें से कुछ जगहों को चुन कर हिसाब लगाना चाहती है तो फिर तो इसके बारे में कोई निश्चय ठीक प्रकार से नहीं हो सकता।

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

उस दिन मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने तात्कालिक 9 करोड़ रुपये की मांग की और फरवरी तक देने की बात कही है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उसमें से कितना आज तक दिया है। अभी तक केवल 1 करोड़ रुपया अकाल के लिये दिया गया है। मैं अगर गल्ती नहीं करता तो बाकी की रकम जो है वह जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के सहायतार्थ है, मुझे जो अपने एक सवाल के जवाब में स्टेटमेंट मिला है उसके आधार पर बाढ़ के सहायतार्थ वह रुपया दिया गया है, अकाल के निमित्त केवल एक करोड़ रुपया दिया है। इतनी भीषण समस्या है और जब कि वहां की एक्सपर्ट कमेटी ने भी 9 करोड़ रुपये की तात्कालिक सहायता देने की मांग की और कहा तो केवल 1 करोड़ रुपया दिया जाना वहां के लिये पर्याप्त नहीं है क्योंकि वहां पर ऐसी अनेक शिकायतें हैं कि फावड़े और टोकरियां उपलब्ध नहीं हैं इसलिये अधिक मज़दूरों को काम पर नहीं लगाया जा सकता, वहां पर कुंएं खोदने की बात है, वहां पर सड़कें बनाने की बात है, लेकिन ये सब काम धन की कमी के कारण रुका पड़ा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसकी आवश्यकता को अनुभव करे और इन आवश्यकताओं के आधार पर तात्कालिक साहयता दे। और इतने वर्षों से वहां जो कार्य हो रहा है उसके लिये जरूरी है कि वहां पर कोई ऐसी एजेंसी भी कायम की जाय जो कि रुपया जहां पर खर्च होना चाहिये वहां पर ठीक तरह से खर्च होता है या नहीं होता इसकी जांच करे।

इस सारे इलाके का एक और पहलू है जिसकी तरफ ध्यान दिलाना मैं आवश्यक समझूंगा, सम्भवतः कुछ लोगों को वह अरुचिकर प्रतीत हो। यह सारा इलाका पाकिस्तान के इलाके में है और सारे पाकिस्तान के बार्डर के हिस्से में जब कि पार्टीशन नहीं हुआ था तो वहां के रहने वाले लोग मवेशियों की ले कर अकाल के समय में उधर सिंध नदी के क्षेत्र में जाते थे और इसी कारण से राजस्थान का यह बीहड़ कैटिल ब्रीडिंग का एक बहुत बड़ा केन्द्र बना। जैसलमेर के बिलकुल बार्डर पर एक 30 मील लम्बा घास का ट्रैक है। आज भी वहां घास उपलब्ध है, वहां पानी है, उसमें घास है, वहां जा सकते हैं लेकिन आज बार्डर असुरक्षित होने के कारण उधर नहीं जा सकते। अब इन सब को नीचे आना पड़ता है। गुजरात में भी आज अकाल की स्थिति है, कच्छ का सारा इलाका भी उससे घिरा पड़ा है। मध्य प्रदेश में लोगों ने मांगा है और वहां पर मवेशी गये हैं। मध्य प्रदेश सरकार से बात हुई थी कि वहां से घास काट कर ले जांय, उन्होंने अक्टूबर में वह आफर दिया और आज दो महीने का समय हो गया अभी तक राजस्थान सरकार वह घास काट कर के वहां से ला नहीं पाई। उसमें क्या उनको कठिनाई है इस बात की जांच करनी चाहिये और अगर इसमें केन्द्र किसी तरह से सहायक हो कर उस घास को ले कर आ सके तो उसको वह करना चाहिये। पंजाब से इस बारे में पूछा था मगर पंजाब से अभी तक कोई आंकड़ा नहीं मिला है इस वजह से पंजाब से उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। लेकिन अब वहां सीमा-रेखा बन जाने के कारण ये लोग उत्तर पश्चिम में नहीं जा सकते, इनको दक्षिण-पश्चिम में आना पड़ता है। ये सारे मवेशी जितने भी निकल पाये हैं वहां से निकले हैं। एक खतरा पैदा हो गया है कि वहा सारा क्षेत्र खत्म हो गया। पिछले दिनों में बार बार यह मांग की जाती रही कि वहां पर ट्यूबवेल आर्गेनाइजेशन ने अनुभव प्राप्त किया है, किन्तु जसलमेर में वह कुल 13 मीठे पानी के कुवें खोद पाई, वहां पर मीठा पानी कम है, आप कितनी भी वहां कोशिश करें वहां पर मीठे पानी के अभाव में कुएं खोदने का काम नहीं चलेगा, वहां मांग की जाती रही है राजस्थान कैनाल के बढ़ाने की। सवाल खड़ा होता है कि राजस्थान कैनाल का काम साधनों के अभाव में कम हुआ है, तो इसके ऊपर विचार

करना चाहिये। पिछले दिनों में एक अजीब चीज हुई कि गंगानगर जिले की जो एग्जि-स्टिंग कनाल्स हैं उनमें भी केवल 50 परसेंट पानी दिया जा रहा है। क्या कारण है मंगला बांध के निर्माण की समाप्ति होते ही जब पाकिस्तान को कांग्रेचुलेट किया गया तब उस समय डा० के० एल० राव ने यह अपेक्षा बतायी थी कि अब हमको पानी ज्यादा उपलब्ध होगा और हमको अपने इरिगेशन सिस्टम से अभी तक जो पानी पाकिस्तान को देना पड़ता था उसको अब पाकिस्तान को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंगला बांध के बन जाने से उसकी इरीगशन की सारी व्यवस्थाएं हो गई और हमको इन्डस वाटर ट्रीटी के अनुसार उनको पानी देने को जो जरूरत थी, अपनी एरिया को स्टार्व करके, उसमें भी बचत होगी लेकिन अभी तक वह गंगानगर कैनाल पर केवल पचास परसेन्ट पानी बह रहा है। मैं पूछना चाहता हूं : अभी भी हम किसी कारण से राजस्थान कैनाल को इन्ट्रस्ट करने के मामले में "स्लैक डाऊन" या "स्टगर" करना चाहते हैं तो हमको साफ कहना चाहिये हमको आशा नहीं है पानी बढ़ाने के बारे में। बजाय इसके कि हम ऐसी चीजों को रेप्रेजेन्ट करते जायं, लोगों को झूठी आशाएं बंधाए जिसका कोई लाभ नहीं है।

इस सारे इलाके में जो दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ है उसे मुझे साफ करना पड़ेगा। आज भी बार्डर में रहने वाले व्यक्तियों, हिन्दू और मुसलमान के प्रश्न पर व्यवहार में अंतर है। हमारे मित्र इसको पसन्द नहीं करेंगे लेकिन आज वहां के जितने हिन्दू कैटल ब्रीडर हैं, उनको तो मजबूर होकर दक्षिण पूर्व में आना पड़ता है लेकिन जो मुसलमान कैटल ब्रीडर है आज वह आसानी से पाकिस्तान में जाता है, मवेशी लेकर उधर गया है, उसके घर के लोग यहां रहते हैं, और कभी भी वह इधर से उधर आता जाता है और यहां का हिन्दू नहीं जा सकता है। हमारे यहां के कुछ शेड्यूल्ड कास्ट के मेघवाल पंथी उन्हीं की देखादेखी वह यहां चौटन तहसील के गांव बागड़ी से 31 अक्तूबर, 1968 को पाकिस्तान सीमा में गये। 8 पुरुष, 8 महिलाएं, 5 बच्चे 24 मील दूर पाकिस्तान बार्डर में पकड़े गए। उनके साथ मवेशी थे। पाकिस्तान के रेन्जरों ने उन्हें पकड़ा और बार्डर सेक्यो-रिटी फोर्स के हवाले किया जिसमें उन सारे लोगों के अलावा मवशी थे 17, गायें, 2 बछड़ियां, 7 ऊंट, 20 गधे, 20 भेड़, 20 बकरियां वापस लौटाई। यहां तक ौक खड़ी हो गई। यह वह लोग हैं जब हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई में मोर्चा खड़ा किया था बाड़मेर के आगे तब उस टेरीटरी में इंडियन फोर्स गई थी और तब वहां की आबादी यहां आ गई। उस समय 18,000 लोग पाकिस्तान माइग्रे करके चले गये थे। वहां राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को मूव कर रखा है कि उन 18,000 लोगों की नागरिकता कम से कम समाप्त करो, केन्द्रीय सरकार ने उन को कोई जवाब नहीं दिया, उनकी नागरिकता बदस्तूर है। 1965 में ये लोग आ गये थे, यह वापस लौट कर आज चौटन तहसील में जेल खाने में बंद हैं, य अपने नागरिक नहीं हैं, उनका क्या किया जाय। आज यह प्राब्लम बन कर खड़ा हो गया है। आज हमें इस प्रश्न पर पूर्ण विचार करना चाहिये। यह अकाल के प्रश्न के साथ हमारी सीमा की असुरक्षा का सवाल बन और यहां के इलाके में ऐसे लोग हों जो कभी भी इधर से उधर और उधर से इधर चले जायें तो फिर यह हमारी सुरक्षा के प्रश्न पर एक बड़ा भारी भीषण संकट खड़ा करेगा। इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर, उन लोगों की तात्का-लिक आवश्यकता पर तुरन्त सहायता देकर उस सहायता को कार्यान्वित कराने के लिये कोई एक स्पेशल एजेन्सी कन्द्र के द्वारा बने और उनको रोजगार दिलाने में हम मदद करें। इस सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में सैनिक जवानों की सहायता लेकर सड़क बनाने के काम में और खनिज उद्योग में मजदूरियां दिल-वाने का काम और अगर ट्यूबवेल खोद सकते हैं, यह काम कराएं और राजस्थान कैनाल

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

के बारे में स्पष्ट स्थिति बताई जाय कि उसको न बनाने के राजनैतिक कारण हैं या आर्थिक कारण हैं ताकि लोगों को आर्थिक निर्माण योजनाओं को कार्यान्वित करने में मदद मिले और हम इस भीषण संकट का सामना कर सकें ।

THE VICE-CHAIRMAN : (SHRI M. P. BHARGAVA) i May I again request Members to cooperate with the Chair as far as the time factor is concerned?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA (Rajas-than) : Mr. Vice-Chairman, sometimes in this House we discuss the flood situation and sometimes the situation arising out of drought and famine conditions. It is really a tragedy of the Indian agricultural situation that sometimes we have droughts and sometimes we have floods. In a way it is a measure of the failure of our planning that w; are faced, even after so many years of our freedom, with these things which could very well be avoided. It is said that droughts are acts of God. That might be true to a little extent but famines are man-made. Drought and scarcity result from lack of rain but this docs not mean that famine should result from that situation. Famines are man-made noi only because of deforestation— that is true to some extent—but due to failure of our Government in its policy to take measures which are within its rights and power to do, to prevent such things from happening. So it is really a very sad situation that we still face these problems which have resulted from neglect by the Government of the basic needs and necessities of vast areas in our country. So these are preventible and the whole purpose of this discussion is that we should impress on the Government what policies and programmes they should adopt so that these things become a matter of the past and after so many decades of freedom at least we do not have what are called) famines in any part of our country. l will confine myself mostly to the situation in Rajasthan which has just been very graphically described by my hon. friend. The situation in Rajasthan this year is really very desperate. Wc are used to minor scarcities and droughts almost every year. These things have not deterred us. The Rajasthanis are courageous people with an infinite capacity to face adverse situations but this year the things are really very serious and they are becoming almost unbearable. There are vast areas which have been subject to famines not only this year but for the last five to seven years and the power of resistance in men and cattle is coming to an end and I would very seriously warn the Government to take note of the situation. If substantial relief measures are not provi ded, men might die on the scale that cattle are doing now. The situation is very very desperate and I would describe it as I go along. There are 26 districts in Rajasthan of which at are affected by famine. More than one crore of people are affected. Nearly 24,000 villages out of 36,000 villages are affected by famine. I will give you the instance about two districts among others which are most seriously affected. One is Jaisalmer. It has a poulation of 1,40,000 out of which 65,000 labourers are working on relief works today which means 45 per cent, of the total population and 75 per cent of the working population—if you exclude children up to 12 years who do go to the relief works— and so 75 per cent, of the working population in Jaisalmer is working today on relief works. So you can judge to what extent that area has been affected. Now Barmer district is also one of the seriously alii ii« d localities. To-day there are 83,000 persons working on relief works and last year there was a famine in Barmer and in March 1966/67, which meant last year, there were 75,000 workers on relief works. March is a very difficult period. March and June are the months which are the worst affected and which would make the conditions much more serious than they are today. What I suggest is, when in March last 75,000 were on relief works, today, in November 1968, the figure is 83,000. It means that still there are the difficult months of March, April, May and June facing them. Therefore the number of persons who will go to relief works for work would increase completely out of proportion to what the things have been last year. So these things have to be taken note of.

The hon. Minister, in the Statement which he laid on the Table of the House, said that in October 1.5 lakh labourers were working on relief works. That is an old figure, ana the latest figure is that three lakh labourers are today working on relief works, and this number is likely to go up to fifteen lakhs as time proceeds and as the people's resistance power growsless and more and more of them would flock to these relief works, and now the number of labourers is increasing by thousands every day. Five and a half lakhs of rupees are being spent every day on these relief works

and on prevision of water and other facilities. WtlJ, Sir, I am saying all this because the help that has been made available by the Government of India up till now is most inadequate, and with the utmost sense of seriousness and alarm almost I may inform this House through you, Sir, and the Ministers particularly, that the Rajasthan Government, because of lack of financial resources, they have issued instructions not to proceed on witli the opening of more relief works. Even yesterday we had a telegram from Jaisalmer district that three relief works, road works and others, had been completed and the Government had not decided whether alternative works should be opened, and t'iere seems to be Government instructions that the work should not be proceeded with, because Rajasthan Government is not sure to what extent the Central Government is going to help them in this respect.

We are very grateful that the Prime Minister and the Minister for Food and Agriculture have visited that area. We are also very grateful that friend? of this House and the other House, like Chandra Shekharji and Momin here, have also gone to that area. They have seen things for themselves. I will request my friend, Chandra Shekharji, to speak about the subject because he has seen things on his own, and he and they havs come back and said that the people are in very high spirits. Even with these adverse circumstances we are not asking for any free doles or free kitchens, as is the practice in many other parts of the country when famines strike them. All that we people want is work and we want to get paid for the work. So the Government. ..

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : जहां काम न मिले, भूमि न हो, कोई धन्धा न हो, खाना न हो, उनके लिए क्या आप यह कहते हैं कि सरकार फ्री किचन न खोले ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं आप से कहता कि वहां पर अभी वह स्थिति नहीं आई है।

श्री राजनारायण : आई है। मैं बीकानेर गया था और वहां की हालत को देखकर हमने फ्री किचन के लिए राष्ट्रपति को लिखा है।

श्री राम निवास मिर्धा : आपने लिखा है वहां पर फ्री किचन के लिए मगर आज भी वहां पर रिलीफ दिया जाता है। लेकिन कोई लंगर बड़े पैमाने पर लगाया जाय, इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई है क्योंकि वहां के लोग पुरुषार्थी हैं। वे चाहते हैं कि उनको काम दिया जाय और पैसा जो कुछ भी मिलेगा उससे वे धान खरीदकर अपना गुजारा कर सकते हैं।

श्री राजनारायण : काम करने के लिए तैयार है ?

श्री राम निवास मिर्धा : जब आवश्यकता पड़ती है तो काम करना पड़ता है।

So we want a definite assurance and a declaration from the Government in this House, Mr. Vice-Chairman, that the Rajasthan Government would be allowed to proceed on and receive as many persons as are ready and willing to work on these relief works.

Now the Rajasthan Government has demanded a sum of Rs. 66 crores, and the Government of India, according to what the hon. Minister said the other day, has sanctioned a sum of Rs. 8 crores. So I do not see bow these figures can be reconciled, the demand for Rs. 66 crores on the one side, and the sanction of Rs. 8 crores on the other side. I hope the hon. Minister would assure us that this was only for the short-term period and funds would be no problem so far as opening of relief works is concerned.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI : Has Rs. 8 crores been sanctioned ?

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I shall explain it later.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : They have announced it.

Now T come to the food grains situation. As again I said, people are prepared to pay for cheap grains if they could have them from the cheap grain shops. Now, Sir, Rajasthan Government asked for an allotment *of* 70,000 tonnes for this month. And all they have got is 35,000 tonnes, out of which a few thousand tonnes have to go to the flour mills and other things.

श्री राजनारायण : आधा ।

श्री राम निवास मिर्धा : जी हां, बिल्कुल आधा ।

[Shri Ram Niwas Mirdha]

With a ration of eight kilos, you can imagine, Sir, it is so difficult to maintain one self. So Rajasthan Government is not in a position to increase it, and every one who has visited that area and who has some knowledge of the situation demands that this should immediately be increased to 16 kilos., if not, at least to 12 kilos. So I would like the hon. Minister to please enlighten us whether adequate foodgrains have been made available to the Government of Rajasthan for purposes of distribution through their cheap grain shops. Now, Sir, even these grains are sold at a very high price. Sometimes they are sold at a price higher than even the market price. I was listening to our radio which broadcasts the prices of foodgrains, and it says that *Joioar* sells at Rs. 69 a quintal in some markets, whereas the *jowar,* which is being sent by the Government of India, was being sold at anything like Rs. 74 a quintal. Same is the case with *bajra,* Sir. The sale price fixed is Rs. 83 a quintal whereas the procurement price fixed for red wheat, and the Mexican wheat is Rs. 78 a quintal, which means that wheat is cheaper than *bajra.* So these disparities and anomalies and these high prices should also be set aside and I would very strongly urge upon the Government that an element of subsidy must be introduced and they should rightaway announce at least a subsidy of 25 per cent, for the price at which these things are sold by the cheap grain shops.

Now, Sir, about water supply the situation is very bad. The Government is doing all it could. It is sending rail-borne tanks, truck-borne tanks- Wells are being energised. Tubewells have been commissioned. But still much more remains to be done. Cattle has been transported. 1 would however like to dispute what our friend, Bhandariji, just said, that the Muslim cattle-breeders have not migrated to the south but have gt>rt? to Pakistan. Muslim cattle-breeders have gone as far as Udaipur, which area you know yourself, Sir—which Bhandariji can immediately verify. Around Udaipur you have Muslim cattle-breeders, not one, but...

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI : I have seen them, and my other report also is equally correct.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Well, Sir, the other report is correct because I would like again to mention, this thing. The whole economy of that area has been such that people go regularly to Pakistan for purposes of grazing and feeding. There is no secret on that. That is why I will recommend that the area must be opened up by roads, a vast network of roads, and that the Rajasthan canal should soon be opened. Otherwise that area would remain uninhabited; uncultivated, and therefore be a danger to the security of the country. That area is unknown. People can't go for miles and miles. Even if there is disturbance on the border, the Government would, take a long time to be informed. So that area has to be opened up, for which I will make a very strong submission.

So, Mr. Vice-Chairman, to sum up, I would like firstly that the Government should sanction enough funds and give the Rajasthan Government a go-ahead for opening any amount of relief works if there are people prepared and willing to come and work in them. Whether the Rs. 66 crore figure is correct, or a little less would do, is a question of mathematics But what we are concerned with is that no one must be turned away from relief works because there is no money, or because of other circumstances. Then, Sir, I will repeat secondly that enough foodgrains should be rushed to Rajasthan immediately and the prices charged be the cheap grain shops should be subsidised at least to the extent of 25 per cent, so that the depicted purchasing power of the people would enable (hem to buy these things if subsidised.

Now, Sir, there is a proposal to have goo tubewells. This is not a long-term proposal but a short-term one, which also Government should seriously consider and sanction so that they could come into being as early as possible, so that they might become available within a month or two, before the worst season of the summer comes. Then, Sir, the two things that I said earlier are, one, that the Rajasthan Canal project should be expedited. I am happy the hon. Ministei for Irrigation is here and I would seriously bring to his kind notice this that the way the Rajasthan canal' project, a project of this importance, is. being treated, it is really very difficult I to understand and it is a vcTy sad state of affairs. This is a project of national importance and this should be expedited

as early as possible. Now this along with a network of roads, if built by the ! Border Roads Organisation, in that j area, it would not only open up that j vast virgin area but would also be of inestimable value so far as the defence i of the country is concerned.

Now, Sir, one small thing I will say before I sit down, and it is that the Central Government somehow has told the State Government that they would not like them to open road works as relief works ; they want them to have minor irrigation works, soil conservation works, which it is not possible in that desert area to have. So I would request the hon. Minister not to insist on opening minor irrigation works and soil conservation works but to permit the Rajasthan Government to proceed on with their road construction work, which is of high importance for the economic development of that area also. Now, Sir, before I end, I will plead that long-term schemes for the permanent eradication of famine in this area should be formulated. As I have just said, about Rs. 50 to Rs. 55 crores have been spent on relief during the last twenty years. But when we asked even a crore or two per year for I rural water supply, the Central Government refused to give us this amount, which means that if this sum of Rs. 55 crores had been distributed and spent judiciously over the last ten or fifteen years, probably the situation with which we are faced at present would not have arisen. I will end by saying what I said when I started, i.e., famines are really not acts of God. They arc there because of the failure of human policies and because the Government and the society have not been able even to fulfil the basic human requirements in vast areas. I hope that some of the suggestions that I have made will receive serious consideration on the part of the Government and that the people of Rajasthan would not be allowed to suffer further than what is the least necessary in the circumstances. Thank you.

SHRI BANKA BEHARY DAS : Mr. Vice-Chairman, from the report that has been placed on the *1* able of the House by the Minister on the 18th last, I am sorry to say that it has not given a true picture of the conditions prevailing in the different parts of the country. 1 hough some parts of Andhra, Mysore, Gujarat, Orissa and other regions have been affected, the area which has been affected the most is Rajasthan. The picture that my friend from the other side, who hails from that State, has given is a grim one and the picture that has been painted by my friend, Mr. Bhandari, is also a grim one. There is no exaggeration in the picture that has been painted by them. If you read the reports about the drought conditions prevailing in that part of the country, you will not find the urgency which the situation demands and the steps that the Government of India or the Rajasthan Government should take. That is why at the outset I want to request the Minister that in future when such repot ts come, whether about flood or drought, they should really present the conditions that are prevailing there. I do not want to go into the details of the conditions prevailing in Rajasthan because my friend, Mr. Mirdha, has given a clear picture of the conditions prevailing there. I do not agree with him when he says that the situation has not developed to that extent where starvation deaths are taking place. Not only the reports that come to me frem our sources, but also statements of public workers from that area clearly show that already starvation deaths bave taken place. Even my friend, Mr. Nahatta of the other House, who has been to that area recently and who has given a memorandum to the Prime Minister of the country, has clearly stated in his report that people in these areas are living on grass and roots. If people in certain areas are living on grass and roots, will the Minister tell us here that they are not dying of starvation or that no starvation deaths are taking place ? When the situation is so grave and really starvation deaths are already taking place in different parts of Rajasthan, we should not mince matters, should not stand on prestige nor tell others thai the situation has not deteriorated to that extent.

I am very sorry that up till now the Study Team that was sent by the Planning Commission has not reported to the Government, as the report that has been placed by the Minister shows. Conditions in Rajasthan have been very acute for the last four or five months. If you read the Delhi press you will find a grim picture, which has been depicted in different papers of Delhi, in the last three or four months. Was it not the duty of the Central Government to send immediately a Study Team to that area to find out what was the real situation ? Is it a fact that because the Study Team has

[Shri Banka Bchary Das]

not reported up till now, the Governmentof India has not been able to make upits mind as to what extent it is goingto give assistance to the Government ofRajasthan ? Mr. Mirdha has clearlystated here that the State Governmentis not in a position to give the greensignal for opening up different work.Why has Such a situation developed ?We know it and even last time when wediscussed the drought conditions in different parts of the country, Rajasthan alsofigured very prominently. My report is that some of the parts of Rajasthanhave been the worst hit, as my friendsaid, Jaisalmer and Barmer. In Barmerdistrict for continuously three seasonsthere has been drought, except lastyear when there was a little rain there.In Jaisalmer district there has been norain whatsoever for the last six yearsand this year, according to my report,there was not a drop of rain there. I amvery sorry to say that though the StateGovernment was realising that such asituation was coming, at the proper timethey did not take any effective step inorder to render any assistance to thepeople of the State, nor did they impressupon the Government of India to cometo their assistance. Only when thesituation went out of control, when reporscame to them that people had startedtaking to grass and roots, when they sawthat cattle were dying in their thousandsbecause of lack of fodder and drinkingwater, they realised the dimensions ofthe problem and they started reliefworks or asked the Government of Indiato come to their assistance. I am vrysorry to say that even after twenty yearsof independence, though the RajasthanGovernment got so many certificates fromthe late Prime Minister of the country,enough has not been done even to tapthe resources of the State. Recentlythe exploratory tubewelJs organisationfeund that in a vast area of Rajasthanthere is enough of subsoil water. Theybave dug sixty tube-wells in those regions,but up till now they have not been able toenergise them. Enough attention has not been given by the Svaie Governmentto have more tubewells, so that wheneverdifficulty arose due to lack of rain, theycould face the situation. So, I entirely agree with my friend that the faminethat has visited that State is absolutelyman-made. Of course, as is natural forhim, he was not prepared to blame theCongress Government there or at theCentre. I realise his difficulty. But the moment he said that the grim situation that the Rajasthan people and cattle are facing in that State is man-made, he squarely put the blame on the Government of India and the Government of his own State for the negligence they had shown because of which the people and the cattle in that area are suffering. Though Rajasthan, a large part of it, is a desert, we know that it is also full of resources. Even the Sindri Fertilisers had to depend upon Rajasthan for their raw materials. I am told that, even at this late stage, if the Government of India will try to help this State, they can exploit the resources and engage the people of this State. 1 may remind the Minister here that the policy of the Government of India is not to create assets out of relief funds, but most of the developmental works which the British Government did in this country were during famine. I know that the entire Calcutta-Madras railway line was built when there was a great famine in the last century. Most of the canal system in Orissa and other places was built by the East India Company or the Government when there was a famine. Even an alien Government, a foreign Government, which was not interested in the development of the country, took advantage of such a situation and created some assets for the future, so that they could meet any future emergency. Why not the Government of India even at this late stage rise to the occasion and take up some of the important projects that were sanctioned or proposed to be sanctioned in that State so that they can give employment to the people ? Ihere are only two questions involved in fnnjine and drought conditions. All the States have suffered under famine or drought either this year or that year. Two years back my State, Orissa, was affected very severely. Last year Bihar was the worst sufferer; this year Rajasthan has started suffering. We do not know, maybe next year some other State may suffer. But shall we not have a long-range programme for fighting this menace that is always visiting this country, because of lack of imagination and lack of long-range programmes ? I want to remind the Minister here that a few years hack the Agriculture Ministry of the Government of India wrote to all the State Governments that they should locate their worst pockets which may be visited by drought in different seasons, so that we could have a long-range programme to assist the State Governments in the different projects, just to help them to

face the future in a better way. But I j am sorry to say that those reports are ′ still in the lockers of the Planning Commission and of ihe Agriculture Ministry : for the last eight or ten years, and nobody has tried to open up those old reports. Many of the State Governments located | tlie worst pockets of their State, they also j gave their projects, but once there is a i good rain, the Government of India ; sits tight and forgets that there might be a famine next year or a drought condi- I tion in different parts next year.

Mr. Vice-Chairman, therefore, I would plead with the Government of India] that as far as Rajasthan is concerned i the primary work for them now is to contact the different Ministries, the | Defence, the Railways, and so on, so that immediately they start some of the work there and by that not only they create assets for that State and for the country but they give assistance in the shape of employment. It is a border State, and in this House we have often discussed that because of lack of border roads our position in Rajasthan is vulnerable from i the Pakistan side. Why not all those plans about construction of border roads that arc lying in the cupboards of the Defence Ministry be opened up and taking advantage of the situation we construct those roads so that on the one hand you develop the State and you develop the defence potential of the country and on the other hand you also give employment to so many people ? I know also that the strategic railway line from Jaisalmer to Barmer is still under the consideration of Government. They have approved it but they have not decided yet to undertake it. Is it not the proper opportunity for them, as the Britishers did, to open up that file, sanction it, and start constructing the earthwork so that lakhs of people of Rajasthan who are sturdy, who are prepared to work, can work in that railway line and also face the severe situation ? So why not take advantage of the situation ? I am very bappy that in the last year when the condition in Bihar was very acute, the Government of Bihar, though it was a non-Congress Government, had the courage to take up so many tubewells, and 1 am told that the number of tubewells that were sunk during *one* year was much more than what was done during the last twenty years. Why not the Rajasthan Government and tl e Government of India come to the rescue of Rajasthan at this moment and tty to evolve a plan so that they can exploit all the sub-soil water the tubewell organisation has found, so that in future Rajasthan is not destined to suffer as it is suffering now ? That is why I would plead with the Minister tl at immediately whatever is possible he should do, but be should also contact the Irrigation Minister who is by his side, the Defence Minister who has so many programmes about border roads, and the Railway Minister who has that strategic railway line between Jaisalmer and Barmer, so that they can undertake those projects during this time so that the famine-stricken people of those areas can be assisted in the shape of employment. I agree with my hon. friend that during famine conditions two things are needed. Relief is absolutely necessary, there is no doubt about it, but the primary need of the people is to give them subsidised food and employment. If you can give them employment and subsidised food, I think there is no necessity of spending so much money on relief work. Nobody likes that people should come like beggers and take food in relief camps. We want every self-respecting person to work hard and earn his livelihood and go to the subsidised grain shop where be can get his own food. Is it not possible for the Government of India just now, instead of spending so much money on relief work—relief work can be taken care of by non-official relief organisations if the proper atmosphere is created— cannot they utilise the money for all tl ose puposes which will create assets which will create employment ? At the same time I would request that they should subsidise foodgrain shops in this State. My information is that wheat is selling at 90 p. per kg. in some of the areas even in the grain shops.

AN HON. MEMBER : 99 p.

SHRT BANKA BEHARY DAS : It is something like 90 to 99 p. But is it not possible for Government, as tbey have done in some other cases, to subsidise the food so that in the cheap grain shops people after working in the evening can go there and get their foodgtains at a very cheap rate ?

Mr. Vice-Chairman, I will not say more about tlis because my timeislimited. 1 would refer to my own State of Orissa. Orissa has always suffered because we have not been able to exploit the water potential in the State. Hardly *14 per* cent of the area in Orissa is under irrigation as a result of which most of the districts are affected by drought. Because of

[Shri Banka Behary Das]

rylone some areas have been devastated) but some areas have been affected by drought also. Two districts in Orissa are suffering under drought conditions. Some members of the Planning Commission went there, saw the conditions, and have given their report. 1 hope, to face the situation that is emerging in Orissa, the Government of India will come to tl e assistance of tne State Government liberally.

श्री चन्द्र शेखर (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रकृति का प्रकोप और मानव की पीड़ा का किसी को दर्शन करना हो तो वह राजस्थान के उन पिश्चिमी इलाकों में जाय जिनका जिक्र हमारे मित्र मिर्धा साहब और सुन्दर सिंह भंडारी जी ने किया है। यूं सारे देश में और सभी प्रदशों में एक या दूसरा क्षेत्र सूखा से पीड़ित है, लेकिन जो अवस्था आज राजस्थान की है वैसी शायद और प्रदेशों के किसी हिस्स में नहीं होगी। मुझे भी पिछले दस पद्रह वर्षों में प्राकृतिक विपदाओं में जहां लोग पीडित हैं वहां जाने का मौका मिला है। लेकिन पिछले दिनों में जो अनुभव मैंने राजस्थान में किया, मेरे जीवन में डोसा अनुभव कभी नहीं हुआ था। मैं कभी सोच भी यह नहीं सकता था कि बीस वर्षों के बाद लोग पीने के पानी के लिये तरसते होंगे। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एक प्रादेशिक सरकार ऐसी हो जिसमें एक स्थायी विभाग अकाल विभाग का बना हुआ हो और बीस वर्षों से वह अकाल निवारण विभाग अपना कार्य करता रहा हो, तो मेरे जैसे व्यक्ति की राय में ऐसा विभाग प्रदेशीय सरकार के लिये और केंद्रीय सरकार के लिये लज्जा का विषय है। बीस वर्षों के बाद भी अगर हम यह मान कर के चलें कि अकाल अवश्ययं-भावी है, वह तो पड़ कर ही रहेगा तो इससे बड़ा निष्क्रियता का शब्द हमारे लिये और कोई नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि प्रकृति और पुरुष का संघर्ष चिरन्तन काल में चलता रहा है। लेकिन विज्ञान के इस युग से प्रकृति के ऊपर विजय पाने के लिये मनुष्य ने जितने अन्वेषण किये हैं अगर उनको इस्तेमाल किया जाय, उनको प्रयोग में लाया जाय तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य की जो विपदाएं हैं, वे कम न हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे देश के सूखा पीड़ित क्षेत्रों की ओर केवल संकेत मात्र करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि यह केवल एक जगह का मामला नहीं। आन्ध्र में,तेलंगाना में और रायलसीमा में बिहार में पलामू, पटना, गया, शाहाबाद, हजारीबाग, सारन के जिलों में, गुजरात के कच्छ और बनासपाटा के इलाकों में, हरियाणा के यहसार, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ के इलाके में, मैसूर के बंगलौर, टुंकूर, मैसूर, कोलार, मन्डिया और चित्रदुर्ग के इलाके में, उड़ीसा के सम्भलपुर, बोलनगिरी, कालाहांडी और सुन्दरगढ़ में तथा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर, जोनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ तथा बलिया के इलाकों में कमी की स्थिति पैदा हुई है सूखे के कारण और प्राकृतिक आपदाओं की बात मैं नहीं करता, लेकिन ये सब कमी के क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर फसल बर्बाद हुई, जहां पर जो पैदावार होनी चाहिए थी उसमें कहीं 80 फीसदी या 50 फीसदी नुकसान हुआ लेकिन राजस्थान की जो कहानी है वह अनोखी कहानी है। 4 दिनों में हम और हमारे कुछ साथियों ने 800 मील की यात्रा की। 800 मील में हम जहां गए, वहां एक ही आवाज सुनने को मिली 'हमको पीने के लिए पानी चाहिए'। हमारे साथ वहां की प्रादेशिक सरकार के मंत्री महोदय थे। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसे स्थान हैं, जहां प्रतिदिन 35 मील से पीने के लिए पानी भेजा जाता है, चाहे वह पानी ट्रकों के द्वारा भजा जाता है, चाहे रेल के जरिए भेजा जाता है। इस साल उस पूरे इलाके में एक दिन भी पानी नहीं बरसा और कहा गया कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं, जहां 5–6 बरस के लड़के यह नहीं जानते कि बरसात क्या होती है, पानी किस तरह से बरसता है। 5–6 बरसों से वहां पर निरन्तर सूखा पड़ रहा है और खास तौर से जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का इलाका तो बहत बुरी हालत में है।

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

महोदया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हजारों वर्ग मील में पीने के लिए पानी न हो, जहां घास का एक पौधा दिखायी न पड़ता हो, रेगिस्तान के जो पौधे हों वे भी सूख गए हों, जिन इलाकों में—जनता के बताए हुए अनुमान से—करीब 2 लाख मवेशी विशेष तौर से गाएं पानी और घास के बिना मर गई हों, जहां पर—खुद हमसे लोगों ने कहा—पौष्टिक आहार न मिलने के कारण बच्चों ो एक्यूट डाइरिया होता है और उसके बाद वह ीमार पड़ कर दो-तीन दिन में मर जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति सहन की जा सकती है ? यह विवाद उठाना व्यर्थ है कि भुखमरी से मरे या बीमारी से मरे; क्योंकि चाहे सरकारी अधिकारी हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, कोई इस बात को विवादास्पद नहीं मानता कि ौष्टिक आहार न मिलने के कारण, जैसा माननीय सुन्दर सिंह भंडारी ने कहा, लाखों लोगों को रतौंधी की बीमारी हुई । मैंने खुद एक मां को बच्चे को गोद में लिए हुए देखा जो शायद कुछ घंटो का मेहमान था । हमारे साथ माननीय डा० मंगलादेवी तलवार थीं, वे डाक्टर हैं, उन्होंने खुद देखा । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी मां की ममता का, उसकी पीड़ा का अन्दाज केवल सरकारी आंकड़ों से लगाया जा सकता है ? उसको देखकर, सुनकर और समझ कर उसका अनुभव-मात्र किया जा सकता है । यह क्यों होता है ? इसलिए होता है ; क्योंकि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन यह कहता है कि हमारे पास साधन नहीं हैं, वित्तीय साधन नहीं हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं । महोदया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीने के पानी के लिए जो योजना राजस्थान सरकार ने प्रस्तुत की है उस पर 5 करोड़ रुपए व्यय का अनुमान है, वे कहते हैं कि 5 करोड़ रुपया अगर उनको तुरन्त दे दिया जाय तो उस इलाके में किसी तरह पीने के पानी का इन्तजाम होगा और 5–7 मील की दूरी से पानी ला सकेंगे, लेकिन 5 करोड़ रुपया हमारे वित्त मंत्री जी केन्द्र से उनको नहीं दे सकते ; क्योंकि साधनों की कमी है लेकिन, महोदया, क्या आपको यह जानकारी है कि दिल्ली नगर में, जहां हम और आप रहते हैं जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से, उसको सुन्दरतर बनाने के लिए 12 करोड़ रुपया हमारी सरकार के पास है ? जब इन बातों की और मैं संकेत करता हूं तो हमारे कुछ भाई, कुछ साथी यह समझते हैं कि ये भावुकता की बातें हैं या मैं किसी को गलत रूप में जनता के सामने रखना चाहता हूं, लेकिन महोदया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश में जहां एक-एक बालिग आदमी देश को बनाने के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए जिम्मेदार हो क्या यह सहन किया जा सकता है कि एक नगरी को जहां चन्द नौकरशाह और चन्द अपने को जनता का प्रतिनिधि कहने वाले लोग रहते हैं, वहां फूल-बगीचे लगाने के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च किए जायं और दूसरी तरफ लाखों मनुष्यों और लाखों पशुओं को पीने के लिए पानी देने के लिए 5 करोड़ रुपए न दिए जा सकें । मैं नहीं जानता, हमारे माननीय शिन्दे साहब के पास इसका क्य उत्तर है, मैं नहीं जानता माननीय मोरारजी देसाई के पास इसके लिए क्या उत्तर है । गोआ के सम्मेलन में हमने कहा की 20 बरसों में हम पीने का पानी नहीं दे सके, गांधीजी के शताब्दी साल में हम सबको पीने का पानी देंगे । अगर यह बात सही है, अगर हमारे भाई सही हैं, अगर हम गांधी जी का समादर इस देश में रखना चाहते हैं तो क्या कठिनाई है भारत सरकार के लिए यह कहने में कि राजस्थान सरकार जितने रुपए चाहेगी पीने के पानी का इन्तजाम करने के लिए व रुपए दिए जाएंगे, चाहे किसी कीमत पर वे रुपए देने पड़े । लेकिन महोदया, जब यह सवाल उठाया जाता है तो राजस्थान सरकार के पास यहां से अफसरों का दल जाता है दो-चार जगह बड़े-बड़े बंगलों में घूम-घूम कर, राजस्थान में, जयपुर में अफसरों से बात

[श्री चन्द्र शेखर]

करके आता है, एक रिपोर्ट दी जाती है योजना आयोग से लेकर वित्त मंत्रालय तक महीनों वे फाइलें दौड़ती रहती हैं और इस तरह हम लाखों पशुओं और सैकड़ों मनुष्यों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। महोदया, मैं नहीं जानता संसदीय जनतंत्र में कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा पथ है जिससे हम आपके जरिए इस सरकार को सुना सकें कि केवल यह जरूरी नहीं कि हम उचित दिशा में जायं, उचित दिशा के साथ साथ गति की भी आवश्यकता होती है? अगर दिशा सही हो और उसके बावजूद भी गति बहुत धीमी हो तो काल की जो गाड़ी है वह हमारे पांव के नीचे से खिसक जायगी। मुझे अफसोस है, मुझे दुख है कि भारत सरकार के जो आज नेता हैं वे गति की आवश्यकता को समझ नहीं पाते क्योंकि गति के साथ और समाज की प्रगति के साथ चलने का इन्होंने ढंग नहीं सीखा। महोदया, मैं यह बात कोई गुस्से में नहीं कहता, म यह बात कोई भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं कहता, मैं केवल इसलिए कहता हूं कि संसद में जो इस देश की सर्वोच्च संस्था है वहां मैं उन लाखों भूखे-प्यासे लोगों की पीड़ा का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं जिन्होंने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर हमसे केवल एक बात की मांग की, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं चाहते, हमको पीने का पानी दो, हमारी मेहनत का उपयोग करने के लिए काम दो। क्या ये दो बातें पूरी करना सम्भव नहीं है?

यह इलाका जोधपुर से लेकर गडरा रोड तक और फिर वापस हमारे मित्र माननीय अमृत नाहटा का क्षेत्र है। यह करीब 42-45 हजार वर्ग मील का क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व अमृत नाहटा साहब करते हैं। हर जगह मैंने देखा कि जिस समय सारे लोग घेर लेते थे, स्त्री-बच्चे, सब एक ही बात पूछते थे कि अमृत नाहटा साहब कब पीने का पानी दिला रहे हो। माननीया मंगलादेवी तलवार यहां पर हैं, उनसे पूछ लीजिए स्त्री और बच्चों की जो दुर्दशा हमने देखी। चाहे सरकारी रिपोर्ट में कुछ लिखा हो, एक-एक सड़क पर 12-15 हजार लोग काम करने के लिए आते हैं स्त्री और बच्चे, खुले आकाश में जहां कोई झाड़ी नहीं, जहां कोई पेड़ नहीं है वे रात बिताते हैं। जिस समय हम गए उनके लिए कोई ऊपर से साया नहीं था, हमने पूछा तो कहा गया कि इन्तजाम किया जा रहा है, शायद राजस्थान सरकार कुछ इन्तजाम कर रही है। महोदया, आप अनुमान लगा सकती हैं कि इस जाड़े की रात में स्त्री और बच्चे घर से 10-12 मील की दूरी पर पड़े हों और उसके बाद यह कहा जाता हो कि इन्तजाम किया जायगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं महोदया, कि अगर इस देश की सीमा पर, गदरा रोड या जैसलमैर के इलाके में कोई बाहरी दुश्मन का हमला हो तो हम क्या करेंगे? हम क्य यह कहेंगे कि इंतजाम किया जा रहा है। सारे भारत सरकार की यह जिम्मेदारी हो जायगी कि दौड़ कर के सीमा के क्षेत्र में जांय और देश की सुरक्षा करें। क्या आज वही स्थिति नहीं है? क्या वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की और नेतागणों की, श्री मोरारजी भाई देसाई की, श्री जगजीवन राम जी की यह जिम्मेदारी नहीं है, माननीय सरदार स्वर्ण सिंह जी की यह जिम्मेदारी नहीं है कि उस इलाके में जांय और देखें? कौन सा काम इस दिल्ली में होता है कि अगर चार दिन ये लोग नहीं रहेंगे तो दिल्ली का काम रुक जायगा? हजारों लाखों लोगों की पीड़ा के सामने दिल्ली में फाइलों का काम, नौकर-शाही के लिखे हुये नोटों पर दस्तखत करने का काम, ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं चाहूंगा कि जब ऐसी विपत्तियां आयें, जहां पर सारी मानवता संकट में हो, जहां पर सारी मान्यतायें संकट में हों, तब भारत सरकार का यह कर्त्तव्य होता है, राजस्थान सरकार का यह कर्त्तव्य होता है, उत्तरदायित्व होता है, कि वह संकट के स्थान पर जांय और वहां जा कर उन लोगों की पीड़ा को देखें।

महोदया, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह सब काम कितनी ढिलाई से हो रहा है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकती हैं कि केन्द्रीय नलकूप खोदने वाले विभाग ने आज से चार-पांच वर्ष पहले कुछ ट्यूबवेल्स खोदे लेकिन उन ट्यूबवेल्स को कमिशन नहीं किया जा सका, उसमें पम्प नहीं लगाया जा सका। कहा जाता है कि साधन नहीं हैं, कठिनाइयां हैं, ऐसी जगहों पर ट्यूबवेल्स हैं जहां पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। महोदया, क्या आप ऐसे बहानों को सही बहाना मानती है ? क्या आप समझती हैं कि दो चार सौ ट्यूबवेल्स लगाने में इनको कठिनाई होगी ? क्या भारत सरकार के पास, चाहे वह खाद्य मंत्रालय हो, चाहे वह सुरक्षा मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, यह साधन नहीं है कि पचास सौ रिग्स ले जा कर के एक महीने के अन्दर पांच करोड़ रुपया खर्च कर के राजस्थान में ट्यूबवेलों को लगा दें। मैं नहीं मानता कि भारत सरकार इतनी पराक्रमहीन हो गई है कि इस छोटी सी समस्या का समाधान वह नहीं कर सकती। लेकिन इसके लिये इच्छा-शक्ति चाहिये, जिस बात की आज कमी है। पैसों की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, इच्छा-शक्ति की कमी है और उस इच्छा-शक्ति को पैदा करने के लिये प्रायः हम कहते हैं कि मौलिक सिद्धांतों पर हमें जाना होगा। मगर सरकार का एक तरीका बन गया है। एक गांव रामसर है और एक बयातू है या कुछ गांव हैं, वहां के लोगों ने कहा कि 35 मील से उनको पीने के लिये पानी लाना पड़ता है। तो एक ओर यह पीड़ा है लेकिन दूसरी ओर मैं आपसे, महोदया, इस अवसर पर कहना चाहता हूं और राजस्थान के उन लोगों का अभिनन्दन करना चाहता हूं क्योंकि हर जगह जहां जहां मैं गया एक जगह भी कोई यह कहने वाला नहीं मिला कि मुझे मुफ्त में खाना दो, मेरे लिये फ्री लंगर खोलो, हर जगह लोग कहते थे कि हमको काम दो, पानी दो, रोजी दो, हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे। दूसरी मांग उनकी क्या थी ? उनकी दूसरी मांग यह थी कि हमको सस्ता अनाज दो, मोटा अनाज दो, सस्ता अनाज दो। महोदया, शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि भारत सरकार का कानून फ्री लंगर चलाने के लिये पैसा दे सकता है, भीखमंगनी की आदत डालने के लिये इस के पास पैसा है लेकिन अगर हम यह कहते हैं कि इस इलाके में 25 फीसदी कम दाम पर अनाज दो तो इसका कानून उस रास्ते में आ जाता है। महोदया, ऐसे कानून को जो सरकार और जो प्रशासन उल्लघन नहीं कर सकती उस प्रशासन के लिये क्या शब्द कहूं, कठोर शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं लेकिन इतना ही कहूंगा कि वह प्रशासन कभी अपने को गतिशील प्रशासन कहने का अधिकारी नहीं रहता।

महोदया, मैं एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमारे मित्र बांके बिहारी दास ने कहा कि सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि सड़कें मत बनाओ कोई और काम करो। कौन सा काम करें वहां पर ? राजस्थान में सड़कें बनाने के अलावा उस इलाके में दूसरा कोई काम नहीं है। यहां से एक्सपर्ट लोगों की एक टीम जाती है, एक्सपर्ट साहब लोग कोठियों में रहते हैं, मनुष्य की आवश्यकता और किसी प्रदेश के अंचल-विशेष की आवश्यकताओं से उनको कोई मतलब नहीं है लेकिन उनको एक निर्देश देने का अधिकार है और वह दे देते हैं लेकिन वह यह नहीं समझते कि अगर वहां सड़कें बनाने का काम नहीं है तो दूसरा काम क्या है ? तालाब खोदने का काम होगा। उस इलाके में दस पंद्रह बीस इलाके होंगे जहां कि सत्तर हजार लोग रोज काम करते हों और मेहनत से करते हों, लोग काम का बहाना नहीं करते असल में जा कर वहां काम करते हैं तो चार पांच या दस दिन में उन सारे कामों को पूरा कर देंगे। अभी जैसा कि श्री सुन्दर सिंह भंडारी और मिर्धा साहब ने कहा कि जैसलमेर के इलाके में चार सड़कें पूरी हो गईं और अब नया काम उनको मिलता नहीं है तो फिर क्या किया जाय ? हमारे सुरक्षा विभाग ने सड़कों की योजनायें बना रखी हैं लेकिन वह कह रहा है, यहां जो केन्द्र में बैठे हुये सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं वह

[श्री चन्द्र शेखर]

कहते हैं कि ये योजनायें दो साल के बाद ली जायेंगी और इस साल पहले करोड़ों रुपये दूसरी सड़कों पर खर्च किया जायगा। यह हमारी सरकार का कोआर्डिनेशन है, एक विभाग से दूसरे विभाग का कोआर्डिनेशन है। क्या कठिनाई है अगर डिफेंस डिपार्टमेंट, सुरक्षा विभाग और खाद्य विभाग, खाद्य मंत्रालय, दोनों मिल कर के कहें कि भाई इस सड़क को ले लो, यह हमारी योजना के अन्दर है और इससे उनको रोजी भी मिलेगी लेकिन यह समन्वय दोनों विभागों का नहीं हो सकता क्योंकि वहां के सेक्रेटरी साहब जो बैठे हुये हैं उनका अलग साम्राज्य है और खाद्य विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, उनका अलग साम्राज्य है। (*Time bell rings.*) महोदया, मैं पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या इतने दिनों के बीच में कभी भी डिफेंस मिनिस्ट्री और खाद्य मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टरों की या सेक्रेटरियों की इस विषय पर कोई बैठक हुई है, कोई समिति बैठी है, क्या कभी इस पर विचार किया गया है ? कम से कम मेरी जानकारी में ऐसा विचार कभी नहीं किया गया। क्योंकि बड़े लोग हैं, इनको फुर्सत नहीं है बड़ी बड़ी जगहों पर जा कर के उद्घाटन करने से और फार्मल स्पीचेज करने से। महोदया, मैं कहूंगा कि इस स्थिति को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

महोदया, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि एक मोटे तखमीने से अगर दो लाख गायें इस इलाके में मरीं तो दो लाख गायों का दाम राजस्थान के हिसाब से कम से कम 5 करोड़ रुपये होते हैं क्योंकि 250 रु० से कम कोई गाय नहीं होती। तो 5 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय धन की बर्बादी हुई और पांच करोड़ रुपये की सहायता हम नहीं दे सके। यह कैसा नियोजन है ? इस नियोजन को किसने शुरू किया?

मुझे दुख हुआ, श्री सुन्दर सिंह भंडारी ने कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान चले गये, मुसलमान लोग चले गये। यह बात सही है, मैंने अपनी आंखों से देखा सारी यात्रा में कि मुसलमान भाई आंखों में आंसू भर कर के अपनी गायों के बारे में किस तरह से जिक्र करते थे और किस तरह से कैटिल कैम्प्स में बड़ी तादाद में उन्होंने अपने पशु ला कर रखे थ और कितनी बड़ी तादाद में वह गुजरात और मध्य प्रदेश में गये हैं उससे यह साफ साबित हो जाता है कि उन की ममता अपने पशु-धन पर बहुत है और वह सबसे अच्छे गोपालक हैं। यह बात सही है कि कुछ लोग पाकिस्तान की सीमा में गये, यह बात हमें भी बताई गई लेकिन ये वह लोग हैं जो हिन्दू थे और 1965 ई० की लड़ाई के जमाने में यहां पर चले आये थे और यहां की पीड़ा और परेशानी से तबाह हो कर के उनको पाकिस्तान जाना पड़ा।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : वह तो वापस ले आये गये।

श्री चन्द्र शेखर : वह वापस ले आये गये होंगे, पाकिस्तान की सरकार उनको लेना नहीं चाहती।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : दूसरे वह हैं।

श्री चन्द्र शेखर : उस घटना को मैं नहीं जानता कि उसमें कितनी सच्चाई है, उसको मैं नहीं जानता लेकिन एक और नमूना देख लीजिये, महोदया। एक गांव है एक हजार की आबादी का। राजस्थान के हिसाब से बड़ा गांव है खेतवाई और इस गांव का एक आदमी भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता, इसमें एक आदमी भी कर्जदार नहीं है, हर एक बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम करना वहां गांव-समाज के जिम्मे है, वहां पर एक सहकारी संस्था है जिसमें हर घर का एक एक आदमी सदस्य है, तो इस खेतवाई गांव की जमीन को ले लिया गया। किस लिये ? इसलिये कि वहां लांग रेंज फायरिंग की जगह बनाई जाय। मिलिटरी के लिये, लांग रेंज फायरिंग के लिये 250 वर्ग मील की जमीन ले ली। इन्होंने कहा कि 50 वर्ग मील जमीन इसमें से छोड़ दो तो हमारे सात गांव जो कि इस रेगिस्तान में बसे हुये हैं उनको नहीं उजड़ना

पड़ेगा । उपर से नीचे तक बार बार दौड़ा, तीन मर्तबा तो मैं माननीय सुरक्षा मंत्री से मिला होऊंगा, वह कहते हैं कि इसको हम बदल नहीं सकते क्योंकि हमारे अफसर नहीं मानते । और महोदया, इसके पहले एक योजना बदल चुकी है । बीकानेर के इलाके में एक एरिया लिया गया था, वहां के महाराजा महोदय ने कहा कि यहां पर मैं तीतर का शिकार करता हूं इसको ले लोगे तो शिकार कहां करेंगे । तीतर का शिकार नहीं रुकने पाये इसके लिये वह स्थान सुरक्षा मंत्रालय ने बदल दिया लेकिन सात गांव के हजारों लोग बर्बाद हो जांय मगर उस योजना में जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महोदया, कि ऐसे सवालों पर भी कोई इस केन्द्रीय सरकार में व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई समिति है, जो कि विचार करे । मुझे इसे दुख के साथ कहना पड़ता है । (*Time bell rings.*) महोदया, मैं दो बात कह कर खत्म करूंगा ।

श्री राजनारायण : बोलिये, बोलिये ।

श्री चन्द्र शेखर : पांच मिनट का समय इन्होंने दिया है ।

श्री राजनारायण : बोलिये, आप हमारा समय ले लीजिये ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदया, ऐसी हालत में हमको और आपको सोचना पड़ेगा । मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सब होता क्यों है ? इस लिये होता है कि जो पीड़ा है मनुष्य की, जो देश की पीड़ा है, इसको अंगीकार करने का ढंग इस सरकार ने नहीं सीखा है । इस सरकार ने केवल सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट को स्वीकार करना सीखा है । हमारे माननीय मित्र शिंदे साहब यह कहने के लिये मुझे क्षमा करेंगे । लेकिन राजस्थान में जिस तरह की पीड़ा है अगर उसको अंगीकार करने का थोड़ा भी प्रयास किया गया होता तो मैं समझता हूं बीस वर्षों में यह हालत बदल गई होती, इस हालत को बदलने में कुछ देर नहीं लगती । लेकिन महोदया, यहां तो सब काम उसी लालफीताशाही के जरिये होता है । हमारे मित्र सुन्दर सिंह भंडारी जी ने सवाल उठाया राजस्थान कैनाल का । मैं मानता हूं, वह एक बड़ा भारी क़दम है जिससे इस समस्या का हल निकाला जा सकता है । आखिरकार कैलिफोर्निया और उजबेकिस्तान भी रेगिस्तान थे । क्या खार का रेगिस्तानी क्षेत्र ही कोई ऐसा स्थान है जहां फसल नहीं पैदा हो सकती । यह धरती सोना उगल सकती है अगर पानी की व्यवस्था हो जाय और यह न केवल राजस्थान की कमी को पूरा कर देगी बल्कि सारे देश की खाद्य समस्या को हल करने के बाद हम दूसरे देशों को भी अनाज दे सकते हैं । कितनी योजना है—सौ या डेढ़ सौ करोड़ रुपये की । वह पैसा कहां से आएगा । पैसा लाने का सवाल एक बड़ा भारी सवाल है इसमें हमारे मित्र सुन्दर सिंह भंडारी के साथ हमारा मतभेद हो जाता है । जब हम यह कहते हैं जिन लोगों के पास पांच पांच सौ करोड़ की पूंजी है, 381 करोड़ रुपये के ऊपर बैठकर जो मुल्क पर हावी हुए हैं उनके हाथों से पूंजी अपने हाथों में ले लो और 45 करोड़ रुपया लगाओ और जनता के कामों में लगाओ तो हमारे माननीय मित्र सुन्दर सिंह भंडारी यह समझते हैं यह मौलिक अधिकारों पर हस्तक्षेप है . . .

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : कानून से करो, डाका मत डालो ।

श्री राजनारायण : : गोरक्षा आंदोलन में जितना चंदा वसूल किया उसमें से दे दो ।

श्री चन्द्र शेखर : मैं पूछना चाहता हूं यह राजस्थान केनाल की योजना क्यों नहीं आती । इसके लिये एक योजना केन्द्रीय सरकार के पास हमारे मित्र नाहटा साहब ने दी "डेजर्ट इरीगेशन आथारिटी" । उन्होंने कहा है कि जैसे दूसरे देशों में आथारिटीज बनी हुई हैं, यहां पर भी एक ऐसी आटानोमस बाडी बनाओ जिसको इस बात का अधिकार हो कि वह अपने फन्ड इकट्ठा करे, वह बान्ड बेचे, वह लोगों से पैसा इकट्ठा करे और उसको इकट्ठा करके इस

[श्री चन्द्र शेखर]

रेगिस्तान नखलिस्तान में बदलने की कोशिश करे। लेकिन यह सरकार एक बुनियादी कदम उठाने में असमर्थ है, यह तो केवल अपनी यथास्थिति की हालत में घिर गई है और इसी का नतीजा होता है कि माननीय सुन्दर सिंह भंडारी जैसे लोग एक ओर राजस्थान की पीड़ा पर आंसू बहाते हैं। मैं नहीं जानता मगरमच्छ के आंसू हैं या इन्सान के आंसू हैं . . .

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : अपना चश्मा ठीक कर लें।

श्री चन्द्र शेखर : दूसरी तरफ जब पूंजीपतियों से पैसा लेने की जरूरत होती है उसके लिये वह तैयार नहीं। महोदया, मैं आपसे कहूं सौ करोड़ डेढ़ सौ करोड़ रुपये के बिना राजस्थान कैनाल योजना रुकी पड़ी है। पार्लियामेन्ट को छोड़ दीजिए, शायद यहां दिमाग ठंडा करने की जरूरत हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं सारे सरकारी भवनों को देख लीजिए, बीस वर्षों में जितने रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडिशनर्स लगे हैं, जितने बड़े बड़े कमरे रखे हैं, एक आफिसर जो चंद घंटे उन आफिसेज में काम नहीं करता, वहां 10,000 रु० का फर्नीचर लगा हुआ है। यह किसके नाम पर होता है। जनता के नाम पर, जनतंत्र के नाम पर . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now you must wind up.

श्री चन्द्र शेखर : संसदीय जनतंत्र के नाम पर महोदया, मैं कहता हूं कि भोग-विलास और ऐश्वर्य के लिये जो धन खर्च होता है उस धन को, उसकी बरबादी को बिना रोके हुए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

अंत में मैं यह बात कहना चाहूंगा नर्मदा का पानी हजारों वर्षों से समुद्र में बह रहा है, न उसका फायदा मध्य प्रदेश को है, न उसका, फायदा गुजरात को है, न महाराष्ट्र को है न राजस्थान को है। भारत सरकार का झगड़ा हमारे माननीय मित्र के० एल० राव साहब यहां बैठे हुए हैं वह जानते हैं वर्षों से चल रहा है, न उसकी पंचायत हो पाती है न उस पर कोई कानून बन सकता है, न केन्द्रीय सरकार में क्षमता रह गई है कि वह दो या तीन प्रदेशों की पार्टियों को बुला कर कहे कि यह पानी समुद्र में बहे उससे अच्छा तो यह है कि यह पानी किसी प्रदेश के काम में आए जिससे देश का भला हो सके।

महोदया, अंत में मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह सारी समस्याएं हल करने का एक ही तरीका है कि केन्द्रीय सरकार में बैठे लोग समझें कि जहां कहीं किसी भी अंचल में मनुष्य की पीड़ा होती है, चाहे वह राजस्थान में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वह आंध्र प्रदेश में हो वह सारे देश की पीड़ा है। अगर कोई सवाल उठाया जाय तो यह उत्तर हम लोग सुन चुके हैं कि मंत्री महोदय अभी कह देंगे : पैसे की कमी नहीं होगी, राजस्थान सरकार में क्षमता होनी चाहिये वहां ट्यूबवेल खोलने की। अगर वह क्षमता नहीं है तो आपका कर्त्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि वह क्षमता उनमें पैदा करें। आप लाएं कानून इस संसद में, अगर कोई प्रदेश की सरकार विकास कार्यों को करने में असमर्थ है, अगर कोई प्रदेशीय सरकार विकास कार्य में अवरोध डालती है, आप आइये अपना प्रस्ताव लेकर संसद के सामने, संसद आपको अधिकार देगी, संसद् आपको पावर देगी उस काम को पूरा कराने के लिये। मैं तो मानता हूं प्रदेश की सरकारें स्वयं इस बात के लिए तैयार होंगी अगर आप उनका साथ देंग तो वह भी आपका साथ देंगी। लेकिन आपके दिमाग और दिल ने बड़े बड़ महलों से रेगिस्तान के इलाकों में जाना पड़ेगा। जब तक गोयन्का साहब को इंडियन आइल के शेयर कार्नर करने के लिये रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय दाद देता रहेगा तब तक राजस्थान में लोग भूख और पीड़ा से मरते रहेंगे। महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप कोई ऐसा उपाय निकालें, हमें कोई ऐसा रास्ता बतायें, कि जब शासन बहरा हो जाय तो उसको सुनाने के लिये कोई ऐसी ऊंची आवाज, शक्तिशाली आवाज हो, जिससे शासन सही रास्ते पर आ सके और जनता की

पीड़ा को, जनता के क्रंदन और रुदन को सुन सके। मुझे दुःख है कि राजस्थान की जनता की पीड़ा और रुदन और क्रंदन शायद आज तक भारत सरकार के कानों में नहीं पहुंची है। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि जयपुर की सरकार भी उस रुदन और क्रंदन को एक सामान्य बात मानती है। इसे सामान्य समस्या न समझ कर इसे एक गंभीर समस्या माना जाय और इसका निराकरण करने के लिये अविलम्ब कदम उठाये जांय।

श्री बालकृष्ण गुप्त (बिहार) : उप सभापति महोदया, मैं न तो राजस्थान में जो दो लाख गायें मर रही हैं और सैकड़ों लोग मर रहे हैं और क़रीब एक करोड़ लोग जो अकालपीड़ित हैं, उनकी दुरावस्था पर आंसू बहाने आया हूं और न किसी किस्म की भिक्षा भावना से प्रेरित होकर ही कुछ बोल रहा हूं।

महोदया, इस संसार में बहुत से सूखे इलाके हैं। आस्ट्रेलिया का दो तिहाई इलाका सूखा है इज़राइल का इलाका सूखा है, चिली का इलाका सूखा है, इसी तरह कैलीफोर्निया, एरीज़ोनिया, न्यू मेक्सिको और नेवाडा के इलाके सूखे हैं। लेकिन वहां से कभी कोई आवाज़ नहीं आती कि कहीं एक भेड़ मर गया या कहीं एक आदमी मर गया या कहीं कोई बेकार हो गया।

अभी चन्द्र शेखर साहब गोयन्का साहब को इस रंग में लपेट रहे थे। असल में तो उनको अपनी उस पार्टी को इलज़ाम लगाना चाहिये जो बीस वर्षों से इस देश में शासन कर रही है और जहां हर प्रान्त में हर साल, कभी महाराष्ट्र में, कभी बिहार में, कभी राजस्थान में, कभी सौराष्ट्र में, कभी मध्य प्रदेश में और कभी माननीय चन्द्र शेखर के बलिया और भोजपुर में अकाल घोषित होता रहता है, सूखा पड़ता रहता है। और जब सूखा पड़ता है तब इन्द्र महाराज का प्रकोप कह दिया जाता है और इन्दिरा जी को बिलकुल बरी कर दिया जाता है। इस तरह की प्रकृति की बिडम्बना दुनिया में हर जगह है। इज़राइल ने उस सूखे में समुद्र का खारा पानी मीठा बना कर और वहां ला कर संतरे के बाग़ लगा दिये, कैलीफोर्निया में अंगूर की बेलों से करोड़ों मन अंगूर हो रहा है और हमारी यह सरकार 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके 6000 करोड़ रुपया विदेशों से ले कर के और 15000 करोड़ रुपया अंदुरूनी, सेठ साहूकारों और बैंकों का और एल०आई०सी० के प्राविडेन्ट फन्ड को लेकर अभी तक इस अवस्था में है कि पच्चीस पच्चीस मील दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। राजस्थान में हमेशा का यह दृश्य है कि औरतें और ऊंट दस पांच कोस दूर से पानी लाते हैं। राजस्थान हमारे पूर्वजों की भूमि है। मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे प्रपितामह भी अकालग्रस्त होकर राजस्थान से बंगाल गये थे लेकिन उस वक्त अंग्रेजों का राज था और कहीं कोई योजना नहीं थी, राजे लोग बैठे हुए मदमस्त होकर दारू का सेवन करते रहते थे, अंग्रेजों को रिसाला देते रहते थे। यहां आज जनतंत्र है, गांधीवाद का युग है, समाजवाद की घोषणा की जाती है, बड़ी बड़ी जनकल्याणकारी राज्य की कामना करने वाली बातें की जाती हैं और हिन्दुस्तान के अंदर राजस्थान, बिहार और सब जगहों में अकाल और भूख से मौतें हो रही हैं। अभी मैं एक पार्लियामेंटरी डेलीगेशन के साथ जलपाईगुड़ी और कूच बिहार गया था, वह टिस्टा नदी में चालीस इन्च बरखा के अंदर सैकड़ों मील इलाका तबाह हो गया है। और करीब 10, 15 हजार आदमी बिलकुल मर गये हैं। करीब लाख, दो लाख आदमी बेघरबार हो गये हैं और इस तरह से वहां पर सड़कों के किनारे आदमी मरे पड़े हुए हैं।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मर कहां रहे हैं।

श्री बालकृष्ण गुप्त : इतने लोग मर गये हैं मगर उनको पता नहीं है। जो लोग मर गये हैं वे लापता हैं या बह गये हैं।

श्री राजनारायण : कौसी में भी बहुत से लोग मरे और बह गये हैं।

श्री जगजीवन राम : लिस्ट इन्हीं लोगों के पास है।

श्री बालकृष्ण गुप्त : चूंकि श्री जगजीवन राम जी ने सवाल किया, इसलिए मैं उन्हीं के क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। जहां पर उनका क्षेत्र है, जहा से वे खुद चुनकर आये हैं। 19 सितम्बर, 1968 को शाहबाद के मजदूर सोशलिस्ट नेता श्री शिव प्रसाद सिंह ने एस० डी०ओ० के सामने प्रदर्शन किया और उनको पकड़कर 200 रुपया जुर्माना कर दिया गया और एक महीने की सजा दे दी गई। भभुआ में 5 साल से सूखा चलता आ रहा है। वहा के लोगों ने जब पीने के लिए पानी मांगा तो उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी गई, उनके कमर में रस्सी डाल दी गई और सब को जेल भेज दिया गया। बिहार में सूखे के खिलाफ बोलने वालों को आज सजा दी जाती है। पांच वर्षों तक तीन पंचवर्षीय योजना में बिहार के गया जिले में और शाहबाद जिले में हमेशा सूखा पड़ता चला आ रहा है। वहां पर कभी भी पूर्ण वर्षा नहीं हुई है। सोन की एक मामूली नहर है और दूसरी नहर के हाई लेवल किनारों के बनाने की बात आज तक पूरी नहीं हुई है। 20 वर्ष के कांग्रेस के राज्य में बिहार में 10,556 कुओं में बिजली दी गई थी जब कि अप्रैल 1967 में जब कि वहां पर संविद की सरकार थी, जो केवल 6 महीने तक रही, उसने दिसम्बर 1967 तक 13168 कुओं में बिजली दी। तीन पंचवर्षीय योजना में बिहार में 1800 कुएं खोदे गये जबकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, मगर अप्रैल 1967 से दिसम्बर 1967 तक 1500 कुंए खोदे गये। जितने ट्यूबवैल्स कांग्रेस सरकार ने तीन पंचवर्षीय योजना में बनाये, यह राशि उससे ज्यादा है जो कि संविद की सरकार ने 6 महीने के अन्दर बनाये। इस तरह से संविद की टूटी-फूटी और बदनाम सरकार ने 20 हजार कुंए बना डाले। क्या यह संकल्प कम है ? मगर कांग्रेस सरकार ने तो संकल्प का शब्द ही गायब कर दिया है। कांग्रेस की सरकार तो जनता के दुःख-दर्द को सुनती ही नहीं है और जब मौत की खबर आती है तब वह जागती है। जब आदमी भूखा रहता है तब ही उसको तरह तरह की बीमारी लगती है और तब मरता है। मगर हमारी सरकार इस बात को समझती ही नहीं है। जब आदमी 20 या 25 दिन तक भूखा रहता है तब उसकी आतें और दूसरे शरीर के यंत्र खराब हो जाते हैं और उसके बाद वह बीमारी से मर जाता है। मगर हमारी सरकार इस तरह की मृत्यु को अकाल द्वारा मृत्यु नहीं समझती है।

आज हमारा देश हमेशा के लिए अकालग्रस्त हो गया है, अभावग्रस्त हो गया है, बेरोजगार-ग्रस्त हो गया है। यह हिन्दुस्तान की क्या हालत हो रही है। जब हम लोग अवाज उठाते हैं, जनता अवाज उठाती है, तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। वे लोग समझते हैं कि हम व्यर्थ में अपनी जबान चलाते हैं और इस तरह से अकाल का हल्ला मचाते हैं। यहां पर जब विद्यार्थियों के प्रदर्शन होते हैं, स्कूल टीचरों के प्रदर्शन होते हैं, नैक्सलाइट वाले प्रदर्शन करते हैं, लैफ्ट कम्युनिस्ट प्रदर्शन करते हैं, तब ही बड़ा भारी विस्फोट होता है और तब ही सरकार के कानों में जूं रेंगती है। नहीं तो इतने लोग राजस्थान में अकाल से मर गये, जनता दुखदर्द से पीड़ित है, तरह तरह की कठिनाइयों का सामना कर रही है, मगर इस सरकार को कोई कल्पना ही दिखलाई नहीं देती है। आज हालत यह है कि लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है और पानी के लिए राजस्थान में लोग 30 मील दूर तक जाते हैं। आज जगह जगह राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है। भारत के सम्पूर्ण भाग में सूखे की स्थिति नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है। हरियाणा के कुछ इलाकों में इस समय सूखा पड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके अकालग्रस्त हैं। विदेशों में हिन्दुस्तान में अकाल पड़ रहा है यह लिखने के लिए एक काम हो गया है। यह कांग्रेस के 20 वर्ष के राज्य का परिणाम है। जब तक हम इस राज्य को नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक जनता का कल्याण नहीं हो सकता है, न अकाल को ही

मिटा सकते हैं, न सूखे को मिटा सकते हैं, न बाढ़ों को मिटा सकते हैं और न ही अन्न की कमी को दूर कर सकते हैं।

श्री जगजीवन राम जी हमारे सामने बैठे हैं। श्री सुन्दर सिंह भंडारी जी ने और श्री चन्द्र शेखर जी ने राजस्थान इलाके का जहां पर सूखा पड़ रहा है वहां का दौरा किया और अपने भाषण में कहा कि 99 प्रतिशत जनता सूखे से पीड़ित है। श्री राजनारायण जी खुद बीकानेर में देख आये हैं कि मजदूरों को टैस्ट वर्क में 1 रुपया 12 पैसे रोजाना मिलते हैं। पी०डब्ल्यू०डी० के आदमी वहां के लोगों से जो काम लेते हैं उसकी पूरी मजदूरी नहीं देते हैं और वे 5 और 10 दिन के बाद आधी मजदूरी उनके हाथों में थमा देते हैं। जिस तरह से उदयपुर के नखलीवाले खुमानसिंह को पांच दिन की बकाया रकम देने के लालच से मार दिया गया था, उसी तरह से वहां के अफसर लोग मजदूरों के साथ व्यवहार करना चाहते हैं। यह सब सुनकर, यह सब देखकर, दुःख होता है और ख्याल आता है कि कब हमारा देश इजरायल की तरह तरक्की करेगा। हमारी सरकार तो समाजवाद का ही नारा लगाती रहती है मगर जिस तरह से कैलीफोर्निया वालों ने, एरीजोना वालों ने, न्यू मैक्सिको, नवेडा वालों ने अपने मुल्क को हराभरा और खुशहाल बना दिया है, उस तरह से कब हमारे देश में स्थिति आयेगी।

आस्ट्रेलिया पहले एक फ्री एन्टरप्राइज देश था, उसने भी अपने यहा भेड़ पाल रखे हैं और जब हमारी गवर्नमेंट को ऊन की जरूरत होती है तो वह आस्ट्रेलिया के सामने हाथ पसारती है। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान की भेड़ें गायब हो गई हैं, उनका ऊन खत्म हो रहा है। वहां पर जितने बड़े इलाके में रेगिस्तान है, जहां पर पहले लाखों की तादाद में भेड़ें थीं, अब वहां पर कुछ हजार भेड़ों की तादाद रह गई है। यह सब क्यों हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।

इजरायल ने अपने यहां सूखे का इलाज कर लिया है, मिश्र कर रहा है और जैसा मैंने पढ़ा सीरिया रूस की मदद से फरात नदी में बांध बांध रहा है। हमारे यहां पर राजस्थान कैनाल है और स्वराज्य प्राप्त होने से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं और वह इन 20 सालों के बाद केवल गंगानगर तक ही पहुंच पाई है। भाकरा डैम का जो पानी राजस्थान को मिलना चाहिये था वह केवल 100 या 150 गांवों तक ही सीमित है। हमारी कांग्रेस की सरकार योजना के बारे में इतना भारी खर्चा कर रही है, इतना विदेशों से कर्ज ले रही है और तरह तरह का प्रचार कर रही है। मगर जब गांव में देखा जाता है तो वहां पर लोगों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं मिलती है। आप गांवों में चले जाइये तो आप पायेंगे कि पटवारी साइफन खोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं श्री जगजीवन राम से पूछना चाहता हूं कि एक हरिजन एम०एल०ए० श्री हंसराज है जिन्होंने छानी तहसील में भादरा गांव के हरिजनों का साइफन बंद कर दिया और जब वे लोग 6 महीने तक लड़े तब जा कर खुला। इस तरह से किसानों को कांग्रेस के राज्य में सताया जा रहा है। इस तरह की जो रोजाने की करुण कथा है और वह संसद् तक नहीं पहुंच पाती है। हम लोग क्या कहें, आज जगह जगह पर तबाही नजर आती है। जैसलमेर जिले में जो सूखा पड़ा है, उसकी हालत के बारे में सब जानते ही हैं। झुंझनु जिले को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है जबकि वहां पर 700 गांवों में से 699 गांव अकालग्रस्त हैं। जिन इलाकों में हमेशा अकाल पड़ता आया है, उन इलाकों को ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है, न वहां पर सड़कें बनाई जाती हैं, न रेलें बनाई जाती हैं। जब कोई काम नहीं बनता है तो इधर उधर पैसा बखेर दिया जाता है और फिर दो तीन साल के बाद अकाल का सामना करना पड़ता है। सरकार के सामने कोई मूल योजना नहीं है जिसके द्वारा हमेशा के लिए अकाल को हिन्दुस्तान से भगा दिया जाय। दूसरे देशों ने अकाल को भगा दिया है और अकाल जैसी कोई

[श्री बालकृष्ण गुप्त]

चीज उन के यहां नहीं है। बेकारी जैसी भी कोई चीज उन के यहां नहीं रही है। एक, दो परसेंट की बेकारी वे लोग वहां रखते हैं और हमारे यहां अकालग्रस्त इलाकों में नब्बे और सौ परसेंट लोग बेकार हैं। शहरों में भी 20, 30 फीसदी लोग बेकार हैं। यह किस तरह की योजना है, यह किस तरह का समाजवाद है, यह किस तरह की सरकार है, यह किस तरह के अफसर हैं? यह तो एक विचित्र चीज है। इस को तो देख कर ही दुनिया के लोग हिन्दुस्तान को बिलकुल हीन दृष्टि से देखने लगे हैं और हमारे लोगों की कहीं इज्जत नहीं रह गई है। चाहे इंदिरा गांधी आस्ट्रेलिया जायं, चाहे साउथ अमरीका जायं, भले ही उन को देखने के लिये लोग कूद पड़ें, भले ही अखबारों में उन की चर्चा हो, लेकिन हम लोगों की, हिन्दुस्तानियों की कहीं कदर नहीं है। सब जगह से हम लोगों को भगाया जा रहा है। कहीं हम को कोई बसने नहीं देता। केनिया में हो, लंका में हो, बर्मा में हो, सब जगह से हम लोग निकाले जा रहे हैं और अकालग्रस्त इलाकों में वापस ढकेल दिये जा रहे हैं जहां पानी और अन्न के बिना हम मर रहे हैं। यह हिन्दुस्तान की हालत है। इस हालत का इलाज मुझे तो इस शासन के रहते जिस तरह की चीजें पैदा हो गयी हैं, उन में कहीं नजर नहीं आता। यदि कभी क्रान्ति हुई और दूसरे लोग गद्दी पर बैठे तो इसी जनता के प्रबल श्रम समूह को ले कर सदा के लिये इस प्राबलम को साल्व किया जा सकेगा।

जब रुपये की बात कही जाती है तो कह दिया जाता है कि हमारे पास 1 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ नहीं है। वित्त मंत्री जी सेठ साहूकारों की तरह से व्यवहार करते हैं। जैसे सेठ लोग अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते हैं उसी तरह से वे प्रान्तीय सरकारों के साथ व्यवहार करते हैं और वह कभी किसी को पर्याप्त पैसा नहीं देते। पैसे के मामले में पिछले बीस वर्षों में उन्होंने जितना पैसा बर्बाद किया है उस का परिणाम है कि आज हिन्दुस्तान के कोष में पैसा नहीं रहा है और हर काम में पैसे की कमी सामने आ कर खड़ी हो जाती है। जिस मुल्क में 50 करोड़ आदमी हों वहां क्या नहीं हो सकता। चीन ने बिना विदेशी पूंजी लिये अपने देश में अकाल को मिटा डाला है और हांग-हो जैसी नदी, जो दुख देने वाली और बाढ़ वाली नदी थी, को बांध कर नहरों में कैद कर दिया है। हमारे यहां क्या हो रहा है। हम आबादी में दुनिया के दूसरे नम्बर के मुल्क हैं। हम चाहें तो लोगों के श्रम से बहुत बड़ी चीजें पैदा कर सकते थे। अगर एक आदमी 3 रुपये रोज पैदा करता तो यह 50 करोड़ आदमी रोजाना 150 सौ करोड़ रुपया पैदा करते और हिन्दुस्तान की आमदनी कमी की दुगनी, तिगुनी हो गयी होती और हम को 5, 10 करोड़ के लिये इधर उधर भागना न पड़ता। जलपाईगुड़ी में लोगों ने मुझ से कहा कि रिलीफ के लिये 20 करोड़ रुपये की जरूरत है और अभी तक सरकार ने दो करोड़ रुपया मंजूर किया है। राजस्थान के लोग तो मेरे पास रोजाना आते रहते हैं। वह कहते हैं कि सरकार ने दो करोड़ रुपया मंजर किया है। यह दो करोड़ रुपया तो वहां उसी तरह से सूख जायगा जिस तरह से राजस्थान के बालू के टीलों में एक दो इंच वर्षा सूख जाती है। मैं क्या कहूं कि किस तरह से यह चलेगा। किस तरह से यह होगा या नहीं होगा। चन्द्र शेखर साहब ने बड़ी लम्बी स्पीच दी और जन संघ को और स्वतंत्र पार्टी को और राम नाथ गोयन्का को उस में लपेट लिया। जिस का दोष है उस का गला पकड़िये। मैं राम नाथ गोयन्का का हिमायती या प्रचारक नहीं हूं। मैं स्वतंत्र पार्टी और जन संघ का समर्थक हूं। लेकिन झुठा इल्जाम दूसरों पर लगाने से अपने आप को उस से बरी नहीं किया जा सकता है। दूसरों की तरफ उंगली उठा कर इंदिरा सरकार को बरी करने की कोशिश, सुखाडिया सरकार को बरी करने की कोशिश या धर्मवीर के शासन को बरी करने की कोशिश अब ज्यादा दिन

नहीं चल सकती । लोगों की आंखें खुल रही हैं और वह देख रहे हैं कि क्या हो रहा है । संविद सरकारों पर छोटे छोटे इल्जाम लगा कर, उन के छोटे छोटे मामलों को बड़ा बना कर कांग्रेस का पुनर्गठन या पुनर्जीवन नहीं हो सकता । यह तो वैसे ही माया ी ोव है । जो राजस्थान की हालत है उस को देख कर कौन हिन्दुस्तानी आज कांग्रेस को वोट देगा । कांग्रेस मर चुकी है और उस ने देश को भी मार डाला है और राजस्थान ही नहीं, सब जगह लोग मर रहे हैं । बेकार घूम रहे हैं, इंजीनियर्स घूम रहे हैं, विद्यार्थी घूम रहे हैं, शिक्षक घूम रहे हैं । आज मंहगाई और बेकारी ने सब ो मार डाला है । और जब तक ये लोग कायम रहेंगे तब तक महंगाई और बेकारी को मि ाने का कोई उपाय नहीं है ।

SHR1 KR1SHAN KANT (Haryana; : Madam Deputy Chairman, this double phenomenon of excess of water on the one. side and thirsty human beings and thirsty lands on the other, this is a re-•curring phenomenon in this country which we discuss in this House every day. We find floods and inundation of land on the one sid;.- and thirsty human beings yearning for water on the other. These two phenomena we must analyse and then try to solve the whole situation. Of course floods have two sides of the coin while drought has only one side. Drought is a much more serious problem than floods because it creates excruciating hunger among the people, which is much more terrible than even the the worst human disease. It adversely affects- the human brain, the human mind and the human body. Of course floods have a ravaging effect because they destroy the standing crops, but they have one good thing also. After the floods disappear, in those areas we have better crops. This phenomenon we see everywhere, whether it is Orissa or it is Bengal or it is Delhi. We know that the 1964 floods in Delhi were ravaging but after the floods disappeared there were good crops. The same thing we find in Bengal and Orissa. But drought has got only one side and that is human misery, human agony and human hunger, which needs to be tackled on a firmer basis by having much better planning. But the way we try to solve this problem shows that planning as lacking in this country. These two problems are facing the same fate as our planning in this country is facing. Drought has to be tackled as a much more serious problem. Madam Deputy Chairman, I am sorry to say that this problem has not been tackled at the national level with all the seriousness and attention that it deserves. Drought and floods have this difference : Floods take place in certain river valleys where some rivers flow but drought is such a calamity that can overtake any part of the country, whether there is heavy rainfall or little rainfall. Even a State like Bihar, which has good rainfall otherwise, had to face famine and drought last year. Bengal which has heavy rainfall had to face famine in 1943. Even Andhra Pradesh which is generally a good granary of rice and other foodgrains had less *of* rainfall this year in August but the position improved later in September. In Madras there is inadequate rainfall and there is scarcity of water if the mansoon fails. So, this is a problem which is an all-India problem while floods is a local problem where certain rivers flow. So, this drought problem needs to be looked into with much more seriousness.

Madam, we have Flood Control Boards, we have flood control plans. But I am sorry to say that in this country up till now we have no all-India drought control plan. Madam, in the 19th century India was a history of recurring famines and droughts and after this a Famine Commission was formed which went into the causes of recurring famines in the different parts of the country. That Commission gave a very good report which was implemented. Madam Deputy Chairman, is it not time that the Government of India should appoint an All-India Drought Commission or a National Drought Commission which should go into the problems of various areas where scarcity occurs because of so many factors ? For example in Rajasthan, Haryana and other places recurring droughts arc there and there is scarcity of water. So, Madam, a Drought Commission must be formed which should go into all these things and evolve a comprehensive plan on the basis of which the Government of India and the States must function. But, Madam Deputy Chairman, my feeling is that the Government is tinkering with the problem. According to the statement of the Government of India, all the districts in Andhra Pradesh were originally affected but the situation later improved, 5 districts of Bihar are affected, 2 districts of Gujarat

[Shri Krishan Kant]

are affected, 4 districts of Haryana arc affected, parts of 16 districts of Mysore were originally affected but the October rains have saved the situation, 4 districts of Orissa are affected, 5 districts of Rajasthan, a border area, have been affected. Eight districts of UP are affected and some parts of Bengal are also affected. So I want to bring to the notice of the House that it is a national problem which needs to be looked into very seriously. The Government of India's statement as laid on the floor of the House only shows that they have been tinkering with this problem with some flimsy schemes which they send to the States and which cannot be implemented and thus they are postponed. The story of how the drought situation is being tackled is a very sorry one. I say this from the statement laid on the Table of the Lok Sabha which says :

> "The draft outline of Fourth Five Year Plan made a provision of Rs. 40 crores for surveys and pilot programmes which would suggest the direction of action necessary for tackling the problem of chronically drought affected areas."

What happened later on ? They themselves say :

> "At a later stage this amount was reduced to Rs. 10 crores."

You know where human misery is there, food scarcity is there, men die because of lack of water and food. The lands get parched. The sum provided in the Draft Fourth Plan was reduced to Rs. 10 crores but later on a sum of Rs. 50 lakhs has been provided in the Budget for 1968-69. Is this the way to tackle drought a problem which is recurring ? It is a shamj that we cannot produce our food and still this problem of drought is not put on a war footing as we are going to put the flood problem. There is no all-India survey to tackle the problem. Some schemes are sent to the States, some survey is done. They say that the maximum they have done. They say :

> "Hue to paucity of funds, it was decided to make a beginning by taking up pilot projects covering an area not larger than an average district, in the 'hard core' of the chronieally drought affected areas in the States of Andhra, Mysore, Madras. Gujarat and Maharashtra."

There is no Rajasthan or Haryana^ Is this the way to tackle the drought situation, a problem which is recurring again and again ? We know that rains are unpredictable. You can control floods, but rains you cannot control. It has been estimated by some official that if there is lack of 1" of rain, there will be a loss of Rs. g crores worth of grains and we have not been able to give that much attention toil.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : Is that the Planning Gommission's calculation ?

SHRI KRISHAN KANT : This was of some official. In the statement they say nothing. They say :

> "A special cell to study the drought affected areas of the States has also been set up in the Central Water and Power Commission."

A cell is created for a problem which is recurring for centuries of years in this country and which cannot be solved easily. This needs to be tackled with full authority and with full strength.

Now I would refer to my sad State of Haryana. This report says something about it but I have some report from the Haryana Government which shows that out of a total cultivated area of 56,75,330 acres, the area which is affected by drought is 28,92,384 acres. It means 50 per cent of the cultivated area is affected by drought and 4 districts are affected by it. The value of the loss is estimated at Rs. 127 crores. The Government of Haryana is trying to do its best. It made an estimate as to what should be done and how much money is required for relief works and for giving water to tin people and fodder to the cattle. Thsy estimated that one crore of rupees would be required but they do not have money. They have provided for Rs. 38-49 lakhs for these works and something is being done but we need money. This is a small backward State. Till now no study team from the Centre has gone to-Haryana to study the effects of drought and to give some assistance. Haryana suffered earlier by floods and now it is suffering from drought. So scarcity is there. It was a backward area when it separated from Punjab and we demanded a subsidy of Rs. 10 crores to be given but till now, because we have not made any noise. nothing has been given. If Kerala makes noiee, the Government

of India will give something but because we are gentle people in Haryana and we do not start satyagrahas or march to the PM's house, nothing is given. I do not know whether it is correct. The Statement has given that out of 82 lakh acres about 29 • 5 acres are affected but on the other hand 82 lakh acres are not in the whole State and out of the districts affected, 29 lakh acres are affected. So even in the way it is presented it is put at the minimum. I would ask the Government whether any assistance has been given and if so, what help has been given to the Haryana Government and the people of Haryana to really tackle the problem. I would appeal that at least Rs. 50 or Rs. 60 lakhs must be given to the Haryana Government to tide over this problem of drought in this country. I would request that this should be done immediately so that we can solve the problem of the poor people of a State which gives very good cattle. If the cattle die there, as Haryana is not industrialised and it is mainly agricultural, there will be difficulty. The State can give very good food. It can be prosperous and can give food to the whole *country* as Punjab has given but their main demand is that they should be given some money. They need water. There were a number of schemes like th? Kishau dam. May I know if they will put some pressure on the Finance Ministry to give *some* money for *the* Kishau darn ? The Sahabinadi dam was accepted in the Lok Sabha but til[1] now it is not implemented. In order *to* savo the cattle wealth of Haryana, in order to make Haryana a. very good granary for the whole country, it is necessary that special attention should be paid and it should not be lost sight of because it is a small State. This is all that I wanted 60 say about Haryana.

In the end may I appeal to the Food Minister that it is time, as I said earlier, that an All-India Drought Commission is formed which should survey the problem seriously in the different States so that it can really give a good report which can be fully implemented in this country but before you do that, we have to take some short-term measures. You must provide underground water and surplus water by diversion or by even control bunding. Secondly about roadworks, it h a good thing to have them but side by side, it would be better if electricity is provided along with water so that small industries can grow which can solve the problem of the people permanently rather than tinker with the problem by phrrt-term measures.

A small electricity provision and water provision are essential, which need to be tackled immediately. Thank you.

4 P.M.

SHRI SITARAM JAIPURIA (Uttar Pradesh) : Madam Deputy Chair man, when the previous speakers were speaking on this subject of national calamity, it was painfully observed that certain light hearted Members ii I can use the expression with humility to them v\ere probably taking it a little lightly. When the Congress Members *were* speaking, some of the Opposition were jeering at them, and when the Opposition spoke, most of the Members in the Congress Benches not only repeated the same process but probably with greater vengeance. It was only when, we found Shri Chandra Shekhar spoke, the. Congress Members were stunned, and the Oposition felt that their views were being expressed to a great extent. I would most humbly submit that problems of this nature, they do not apply to any single political party, nor to any individual State, but they are problems of the entire country, and unless and until the entire country is kept in view and associated with this grim situation and find a solution for it, I doubt very much that a problem of this magnitude can be tackled in this manner. I was also a little pained when I found that some of my friends here were displaying a sense of special patriotism when they displayed that giving relief to the distressed was only the monopoly of a few *khans'* representatives or workers' well-wishers or persons who were less privileged than their few counterparts. I am afraid facts speak otherwise. If you go to any of these famine and drought-stricken Areas, and if any one of you have visited them, I can say without any fear of contradiction that in most of these places voluntary organisations are doing the work more successfully compared to any Governmental organisation or, if I may submit, even to a political organisation if any. You would not have forgotten the year 1943, when there was the famous famine in Bengal. I was a student at that time and I used to read newspapers. And I read in the papers that they were completely man-made famine conditions. I also agreed with that assessment at that particular time, and even today I would think that the prevailing drought conditions are also man-made. Even with regard to a small part of the country— I refer to Bengal in relation to the whole country—it was considered then to be a

[Shri Sitaram Jaipuria] man-made famine. And now, after full twenty years of independence, even now the conditions are such; whether we call them drought condition or badly drought-stricken condition, or famine condition or badly famine-stricken condition— the degrees may differ from place to place— the fact remains that we are still living in an era where the conditions are full of famine and things like that. But curiously enough, today the blame is thrown on God Almighty. No doubt I do have faith in God Almighty. I also realise that God Almighty is all powerful. He is capable of showering blessings and is equally capable of taking the blame on Himself. But let us not forget the old saying that Heaven help those who help themselves. Is it a fact, are we all satisfied, sitting in this House, whichever party we may belong to, and whichever Government is in power in whichever State, or in the Centre, that all that we possibly could do, we have done in this regard ? I am not sure we have not done it. If we are true to our conscience and if we search for an answer within our own hearts, we are sure to get the reply, "No, we have not done all we should have done."

[THE VICE CHAIRMAN (Shri Ram Niwas Mirdha) in the Chair]

In the Statement that has been placed before the House, Mr. Vice-Chairman you will find that on page 8 it has been said that while even in Punjab the drought was there, but because of the assured irrigation the effect is not going to be heavy. May I ask in all humility, if that be the case, if assured irrigation can reduce the arena of the drought, what it was that held up the Government of India not to provide these irrigation facilities all over the country ? Plans are made keeping everything in mind. Nature's favourable response may not be forthcoming in any particular month or in any particular year or even in a particular decade; and knowing that fully well, should we not have acted to the extent human ingenuity could go ? I can realise and appreciate that in the first few years of our planning period we might not have been able to plan the programmes successfully and beneficially wherever such programmes were required to the extent—as we would wish them to be. But after some time at least we must be ablf to see that the experience of the past Is taken advantage of. Now have we given that cushion in our plans to assure that, wherever the floods occur or wherever famines come up, a certain minimum arrangements is assured to take care of them, so that a situation of this type do not occur time and time again ? Here again, Mr. Vice-Chairman, what do we find from the different statements placed in Parliament or before the public from time to time. Whenever any new step or any particular programme is placed before the public, very high hopes are raised in the minds of the public by the sponsorers of the programmes but ultimately, when the time allowed for their implementation comes to an end, we always find excuses for their non-implementation and blame one person or the other, one party or the other, or even blame God as and when such a course suits. I would most humbly submit that, while political individuals may indulge in luxuries of this type, from time to time for the sake of some personal name or personal gain—which they would know better—so far as the Government is concerned, the Government has got to place before the public and the Parliament only such of the statements, such of the figures, such of the plans and designs which they are pretty sure to achieve. And if the Government is not able to achieve the plans— may not be able once or twice or even three times—then I would most humbly submit that the Government has got to realise that there is something wrong with their planning, that there is something positively defective which needs to be seen in retrospective, it needs to be seen as to where the mistake lies. I do hope the Government will look into this objectively. And the. future plans, let them not be over-optimistic ones let them not be catchy ones. Let them be those where the people would say that our plans arc good and useful. But let the plan be of a nature which will be practical to be implemented. I have in mind when I make this statement, Mr. Vice-Chairman, the condition of Bihar. In Bihar, if I remember, it was said earlier that there will be tubewells and electricity all over. And if these tubewells and this electricity had been made available as promised, there would be plenty of water and plenty of electricity , and no difficulty. But today Bihar again, a large part of it, is facing drought conditions. Why is it so ? It is because all those promises that were made and the plans that were proposed to be implemented could not be kspt.

Talking about Rajasthan, many of my friends have narrated the pitiable condition Rajasthan is in. In fact, this

drought in Rajasthan, in certain districts, has been going on for the last two or three years. But the new dimension that it has acquired in this year has added to the problem and has focussed public attention all over the country to a very great extent. Why should it have happened, why should it not have happened, is a matter of opinion. Here also I am constrained to say that in many States the figures by the State Governments and by the Central Government do not tally entirely. In the matter of Rajasthan, in the statement that had been placed before this House it has been said on page 17 that the Rajasthan Government is still assessing the effect of the famine conditions in many districts, surprising indeed. May I a»k the Government through you, Sir, if, in spite of these disturbing conditions, which have been lasting for such a long time, even now, the assessment is still going on and they have not been able to give the figures to the Government of India? Of course they must have been able to assess it because their public statements do indicate that they know where the calamity is, they know which areas are such where relief is needed and I know that the Chief Minister himself has been going from city to city to collect aid, charity and assistance to relieve distress in the drought-stricken areas. But it is not convenient either for the State Government or the Central Government to disclose those assessments. A situation in which about 16 lakh milch-cows and 41 lakh other cattle have gone out of Rajasthan I think is a situation which will not only be an immediate problem for the State but it is a problem which will take 20 to 30 years, perhaps even a generation, to be remedied. I know in many places cows have been sold for Rs. 2 to 3—not that this was their price—knowing fully well that at this price they will be able to get rid of them because they are not able otherwise to feed them. If that be the condition, when we are short of milk all over, when milk colonies have been constructed in many important cities which are not in fact able to cater to the requirements of milk in the big metropolitan cities why could not the Government machinery have moved in such a way that these cows could have been prevented from dying ? They could have been broughi over to these places where shortage oi milk continues to exist. Not only that; Mr. Vice-Chairman, I am told thai there have been instances like in Kolaya in Bikaner District where there is ai important deity and a shrine where 2; persons have died of starvation, because they were not given theii wages while they were employed in the relief works. This is a very important point which has to be enquired into. Nevertheless the fact remains that unless and until the Government is in a position to take such steps which are necessary for preventing such occurrences which may happen in any country anywhere in the world, I think no amount of relief measures is going to be of much help.

Here again the question is, what are the long-term measures and what are the immediate measures because both will have to be given due importance. I would say here, Mr. Vice-Chairman, that the conditions in the States differ from one State to another and bearing this in mind the States will have to be given what is most amply suited to each State. Take Andhra Pradesh for instance. Some of our friends in Parliament here had mentioned earlier on 30th August 1968 about the acute drought conditions and later on about the cyclone. Now these things may not be visualised to the fullest extent but certainly to a certain extent it can be seen what the conditions are and what the conditions are going to be. In Orissa for instance in 1965-66 six to eight districts were drought-stricken.

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa) : Nine districts.

SHRI SITARAM JAIPURIA : In 1967-68 there was the cyclone which brought about drought conditions in eight more districts. In 1968-69 there were practically no rains and the conditions became still worse. And on the top of that, Mr. Vice-Chairman, it is most surprising that as against Rs. 5*50 crores recommended by the team the actual amount paid was only Rs. 2*50 crores. It also perturbed me when I read the word 'advance'. What does this word 'advance' mean ? Does it mean that i this flood, drought and similar other conditions are purely a matter for the State Governments to deal with, that the State Governments can get loans from the Central Government which they should repay later on thereby I increasing the States' indebtedness to I that extent ? Either you are able to *I* give immediate relief, settle them properly, or progress is bound to suffer. Not only to Orissa but on page 19 of the statement it has been mentioned that an amount of Rs. 1 crore has been advanced to Rajasthan as loan. I would suggest that instead of giving these loans, it is aid

[Shri Sitaram Jaipuria]

that should be given by the Central Government so that this important problem which is affecting entire country is tackled more progressively and more effectively.

Sir, I referred in the beginning of my speech to voluntary organisations. It has been mentioned in the statement on page 19 that voluntary organisations have been doing a certain amount of work and creditable work. I would like the Government to very categorically state what are the places where voluntary organisations are doing and can do better service and what sort of service is needed out of them. So far the experience of. . .

(*Time bell rings.)*

SHRI LOKANATH MISRA : Sir, other speakers have taken 20 minutes. My party being the major Opposition he should at least be given 20 minutes.

SHRIMATI YASHODA REDDY (Andhra Pradesh) : He is a new member of the Swatantra Party and this is his maiden speech from there.

SHRI SITARAM JAIPURIA : Whether I am a new member or an associate member the records would show but. ..

SHRIMATI YASHODA REDDY : I am subject to correction; I am told he joined the party only recently.

SHRI SITARAM JAIPURIA : To my learned friend I would only say that while I am an associate member of the Swatantra Party I have been always independent but my friend has always been in Swatantra in mind, body and in spirit.

SHRI M. RUTHNASWAMY (Madras) : Body Congress; soul Swatantra.

SHRI SITARAM JAIPURIA : While on page 19 of the statement it has been said that the voluntary organisations have been doing a lot of work I think it is time that the Government should publicly declare or make the State Governments declare in which particular areas what particular work the voluntary organisations should do. Experience has shown that wherever voluntary organisations have worked people have got greater satisfaction from them than from the Government agencies and it is bound to happen because the Government agencies are doing this work at the lower level generally as part of their duties that they have been assigned to do. It may be that the top people are more sympathetic and they are doing it with the desire of giving relief to the distressed but the voluntary organisations, when they start their operations, start with this basic idea in their mind. It has been seen that many of the State Governments are trying to collect funds from the voluntary organisations and institutions and utilise them through the Government machinery. The time has come when the Government should assign a certain amount of responsibility to the voluntary organisations to carry on the work which the Government agencies have been doing so far. I may refer here to subsidised food scheme. I known there are a number of organisations and institutions which are interested to distribute foodgrains at subsidised rates in certain areas which may be agreed upon by the Government but the Government is not prepared to give food at subsidised rates to them. They are in fact prepared to further subsidise it and I would humbly suggest that the lion. \Iinister may look into the possibilities of giving them foodgrains and fodder at subsidised rates so that these voluntary organisations may be able to distribute them at further subsidised rate and if necessary under the guidance of the Government if the Government is very keen about it and I am quite certain that people will get greater relief that way.

There are only one or two more points that I want to make. Much has been talked about deep tubewells. Well, I do not doubt the sincerity of those who have been trying to do a lot but nothing that they do is sufficient. Whatever may be their intentions I am afraid their actions do not prove that and it is in that context I am saying all these things. Minor irrigation programmes, etc. should be looked into carefully. Sim-lady the agricultural educational scheme which get a fillip some years back appears to have been slowed down in the last few years. It is necessary that agricultural educational schemes are pushed through. Of course it is not necessary that there must be B.Sc. in Agriculture or highly educated peisons but they must be persons who know the task, who have the knowledge of agriculture, knowledge about seeds, about manure, about irrigation and things like that, so that I may be able to actually help the farmers in the different areas so that these farmers help the Stales to which they belong.

There is one more point. Experience has shown so far that whether it is tube-wells or electi ification cr fertilizers or better seeds oi improved techniques, the States which have already made some progress compared to other backward States in the country get greater benefils, greater amount of fertilizers per acre of land under cultivation, or water or electrification. If balanced regional development has been accepted as part of our developmental schemes by the Planning Commission there is no reason why the Central Government should not ensure thai such of the areas which arc regionally unbalanced are given extra facilities so that they can come up to a certain standard and thus become equal partners in the progress of the country and contribute to the prosperity of our great nation.

Mr. Vice-Chairman, in the end I do hope that this problem will not be dealt with purely as a party matter or as a State matter but as a matter which concerns the entire country and will be given a national importance so that such calamities and occurrences of this magnitude may at least be avoided if not completely stopped.

Thank you.

DR. (MRS.) MANGLADEVI TAL-VVAR (Rajasthan) : Mr. Vice-Chairman, the problem of drought and that ol flood is a national problem. Drought is not confined to any one particular State or area and, therefore, I agree with what the previous speakers, Mr. Kiishan Kant and Mr. Jaipuria, said. Mr. Krishan Kant suggested that there should be a drought commission on the national basis and it should go into the causes and the long-term and short-term remedies for this very distressing condition. At the same time, I agree that it should not be a political problem for any particular party. It is a national problem and should be approached on those lines by all the political parties. Also, the people of the country, voluntary organisations and philanthropically-minded people should pay greater attention and render help to the people in distress.

Today I shall confine myself to Rajasthan for two reasons. I have recently been there and I feel thai the conditions there arc really heart-rending. The two districts that are very badly affected by drought are Barmer and Jaisalmer. In Jaisalmer district there has been not rain for the last six or seven years. In Barmer district there was some rain last year, but this year there has been an absolute failure of the rain. Therefore, conditions there are really such that you have to see them to believe them. The cattle wealth is the backbone of the people there. There is no other business for them. There is no industry, there is no agriculture. They used to live on this cattle wealth and that has been destroyed. Over two lakhs, they say, have died. Those that are remaining have become so weak and emaciated that for all practical purposes they are unlit for giving milk or do any other work. Therefore, they had to migrate and they had to be taken out. Lakhs of them have gone to the adjoining States of Madhya Pradesh, Gujarat and other good parts of Rajasthan. A large percent-tage of the wool that is produced in India comes from Rajasthan and it is exported. For instance, the people of that area did not like to sell milk because the proportion of human population to cattle population was 2 to I. Therefore, there was no need to sell milk, but they used to sell ghee. They used to drink milk and they used to have "Ghhach". It is a great source of food and nourishment for them. I may say, as has been stated, that the Government of Rajasthan is doing its very best and it is very actively interested in the welfare of the people. They are doing their best to help them from every point of view. Some voluntary organisations arc also providing fodder and drinking water to the cattle. Now, the problem of cattle is more or less solved in the sense that those that have died have died. Those which had to migrate have gone out. For those which are in the process of migration, there are centres or camps and arrangements for fodder and water have been made. They are being looked after.

Now, I come to human welfare. The problem is very great. Sir, as you yourself have stated, in a short time there would be some 15 lakhs of people wanting relief works. It is beyond the capacity of Rajasthan Government to provide some Rs. 32 crores that will be required to pay as wages. There wages have been enhanced. They are now paying Rs. *1* 50 for a man, Rs. i*25 for a woman and Re. i-00 for a child above 12 years of age. Three lakhs of them are already employed. Lakhs of rupees are being spent every day. Therefore, as yourself have said the Rajasthan Government is actually in the process of issuing orders not to open more relief works, because it cannot provide money. A

[Dr. (Mrs.) Mangladevi Talwar]

calamity of the magnitude that has fallen on Rajasthan is not the responsibility of the State Government alone. I would appeal to the Centre to give Rajasthan, either a grant or a loan without interest so that it can take up this work, so that human beings are saved from destruction. More than any thing else, human beings require foodgrains. What is happening? We are able to give them only 8 kgs per month. This is very little foodgrain, leave alone anything else. Fifty per cent of them are suffering from night-blindness. Because they have no vitamins in their food, because of the lack of vitamins A and D, it is causing night-blindness among men and women. After it gets dark, they cannot see. What about the children? You can see thousands and thousands of children, all small and up to the age of sixteen, all suffering from malnutrition. They are suffering from many diseases because of malnutrition. Lack of vitamins makes their resistance very low to all types of diseases. These children are suffering from various kinds of diseases and there is no doubt that they are succumbing to these deadly ailments, which only a healthy child can resist. Also, during this cold weather, many families, especially women and children, are suffering. I may tell you that we have visited many centres where the relief workers are doing their work. Over fifty per cent of them are women and children. The men have either gone out with their cattle or they have gone farther away to the project areas. For instance, they have gone to the canal area, leaving their women and children. They cannot find work nearer their homes. They had to walk or live several miles away from their homes. Many of them are living in the open. You can imagine their plight. You can imagine the cold weather to which they are exposed. You can imagine their suffering. They are half-starved. They have no food, they have no water, they have no milk. They have no "Chhach". They have nothing substantial to live upon. So many Members have already drawn attention to the acute shortage of water. I would also like to say that this acute shortage of water is very distressing to the people. The first thing women say is, "When are we going to get water for us, for our children ?" The Rajasthan Government are doing their best. They are sending water by trucks, by rail. Sometimes mechanical devices break down and sometimes they cannot leave. Every other day the water is supplied. But sometimes they cannot reach even for more than two days. Then you can imagine what it is. For . each family only rationed water is supplied. That is the state of affairs. In 1968, when technology has improved to the extent that man is reaching the moon, that in our country lakhs and lakhs of people and children should be thirsting for water is something that is a challenge for our nation, a challenge for our Government. Therefore, I request the Central Government—because the State Government cannot dig so many wells as are required—to view this as a long-term project and provide water to these areas and thereby solve this problem, because lakhs and crores of rupees are being spent only on this recurring expenditure of taking water from one place to another. So, this has to be done on an urgent war footing if you want to save the people and if you want to save that area. As somebody has also mentioned, it is a border State and many people have left their homes. You can drive for miles and miles without coming across any living thing leave alone a human being. Therefore, that whole area is deserted. It is in the interests of our security that people should inhabit the area. Therefore, the security of our border which is a very very dangerous border should be looked after.

I would like to say another thing that the completion of the Rajasthan Canal should be expedited and the Centre should look into it because the State Government would not be able to spend that amount of money. Also in Jaisalmer area the Rajasthan Canal water would not go and therefore that area will not be supplied with water with the Rajasthan Canal. Therefore, Narmada water should be supplied or some other project should be taken up and that area should be supplied with water. It will become a granary not only for Rajasthan but for the whole of India. The land is so fertile, the land is so good therefore it should be given water.

Then, Sir, I have already mentioned that thousands and lakhs of men, women, and children are working there. They are underfed, they are under-nourished they do not get the proper amount of food and also the quality of food that is required for the growth of children is not provided to them. I therefore appeal to the Health Ministry, the Ministry of Social Welfare and also the Central Social Welfare Board to provide vitamin tablets for the children and for expectant

and nursing mothers if we want to save our children and our future generation. They should also provide milk powder or some other protein substitute for the children because if they do not get protein in sufficient quantity, the children will suffer from a disease which is almost incurable and will not survive; if they do survive, they will not be healthy. Therefore, it is a matter of great concern to us, to the Government and to the people, and 1 appeal to the Government as well as to the voluntary organisations to send these things to those areas and save our children from long term disease and weakness which they will have if they do not get these things.

Then one thing. The Minister of State of Food is here. Eight kg. of foodgrains for one month are inadequate from all standards and much more so for the hardworking people from the border area of Raja than. Therefore, their foodgrains ration under any circumstances should be increased to 10 or 12 kg. They do not want wheat. They say : give us coarse grain, give us *makhai,* give us *bajra* or *jowar;* but give us good quality and insufficient, quantity, at least 10 to 12 kg. per month. So that they can eat at least coarse grain as they have nothing else. They have no *dal,* they have no *subzi,* they have no milk, and they have no "chanch" which they used to have. It is very essential that the ration of foodgrains should be increased. What has happened in Rajasthan? They had not anticipated the terrible drought this year, because many of the farmers thought the rains would come, the rains would come. What happened ? Whatever foodgrains we had produced were sent out to other States. That is why Rajasthan has no foodgrains to give to its own people. This is also a very special circumstance which has arisen in the State of Rajasthan. Rajasthan was never in need of such an amount of foodgrains, never lacked foodgrains so much, but this year it is essential that the Central Food Ministry should consider this very very urgent request from Rajasthan.

SHRI C. AGHUTHA MENON (Kerala) : Mr. Vice-Chairman, the terrible calamity that has befallen the State of I Rajasthan has been described by various J speakers. We all sympathise with the I people of the State and we all want something immediately to be done so that lakhs of people and lakhs of cattle could be ' saved. I will not take your time with a reiteration of the terrible tales of woe] that confronl Rajasthan. I think I should rather confine myself to the suggestions that I have to place before the Government for immediate action. Sir, the General Secretary of our party along with the other comrades have visited the various parts of Rajasthan and have come across terrible tales of woe. We have also submitted a detailed memorandum to the Prime Minister about the action to be taken. So I will not go at length into all the matters mentioned in the memorandum. I would only draw the attention of the Government to things which are to be done, which are urgent. The first thing to be done according to us is to declare Rajasthan as a famine-stricken area and take immediate action under the famine laws. That is to say, relief work should be immediately started and the people should be provided with employment. According to our estimate, the State will have to provide employment to at least 15 lakhs of people and not only for a few weeks but for months together, at least up to June, ig6g because, on account of the failure of rains in the season the terrible conditions created in that part of the country are not going to be changed in the course of a few weeks. So, there will have to be a long-term programme for providing relief work in order to provide employment to lakhs of people. The second thing that has to be done is to provide water to those people. *Here* we have heard terrible tales of suffering on account of scarcity of water. But the interesting thing in Rajasthan is this. Even now there are tubcwells existing which are not functioning. I do not want to take the time of the House by reading parts of the memorandum. But attention should be drawn to certain instances in which very good tubewells capable of supplying water to the extent of about 25,000 gallons a day, even such wells are not functioning because of some administrative difficulties. I cannot understand those difficulties; when such a famine is there and cattle and people are dying, when people are starving, what kind of administrative difficulties can possibly be there in providing people who are thirsty with water, I cannot understand. Any how, if there is any red-tape it has to be cut and water should be supplied to the people.

Then, Government has also to open cheap grain shops. For that purpose, it will be necessary that *the* Central Government should supply adequate grains to the State Government because the State Government, as that hon. Member

[Shri G. Achutha Menon]

has just now said, are not in a position t° supply all the foodgrains needed. According to our estimate, two lakh tonnes of foodgrains should be supplied every month to the State of Rajasthan so that they can be supplied at a reasonable rate to the people from the cheap grain shops.

Another thing is the supply of fodder-Fodder has to be supplied and depots have to be opened up in all the centres. For that purpose, on an emergency basis fodder has to be collected from all the neighbouring States and they have to be brought by railways or by trucks or by whatever means available. And that fodder has to be supplied to people of that locality.

Another suggestion that I would make in this connection is that an All-Party Relief Committee should be set up. After all here is the question of relief work. In anything politics do always come up. It is an unfortunate thing which we cannot help. The only way to obviate the difficulty is to form an All-Party Committee in which all the parties are represented, in which there are non-officials and nonparty people also; and also those who are genuinely interested in relief work should find a place there. They can collect funds from the people of their localities; They can make an appeal to the other States also. And I am sure that nobody will be found wanting to come out with help on a liberal scale for the suffering people of Rajasthan.

It is also necessary to take up some of the long-range projects. Mention was made of the Rajasthan Canal Project here. It was envisaged in 1952. It was intended to supply water to 35 lakh acres of land. If we are in a position to complete that within a reasonable amount of time, much of the food scarcity which we face not only in Rajasthan but taking India as a whole, will also be obviated and this part of the country which is now a desert will be a land flowing with milk and honey, and in plenty. That is one thing.

Another thing is that the Luni Barrage Project which has been shelved due to low return potential should be taken up and completed. Apart from other things, it will raise the water level in the districts of Jalore and Barmer very much.

Then, we should also pay attention to the construction of tubewells because in most of the areas it will not be possible to have any irrigation works or canal works but tubewells can be constructed in plenty. You must have a programme by which within the course of one or two years we will be able to construct many tubewells in several parts of the famine-affected areas, and they can be got commissioned.

Sir, Rajasthan now appears to be a desert, and it is one of the poorest parts of the country. But it is very well known that there is a big potential of gas. Just across the border, outside, the Pakistan Government has been able to exploit their gas potential land they are even selling it. So, if we make a geological survey of this part of the country, it is very likely that we will also be able to exploit the gas potential that is there in Rajasthan and then a lot of interest will come up and developmental activities will also spring up there. In this part also it is possible to develop them and we should not allow this part of the country and its people to suffer because of neglect. We should take it up as a national problem. It is not only a question of Rajasthan alone. The State of Rajasthan may not be able to cope with all the problems that they are faced with because of lack of finances. We know that many of the States are not able to tackle all the problems that they face because their financial capacity is very limited. In the case of the State of Rajasthan especially, its budget is not very much and its resources at the present moment are not also very much. But the problems that it is facing are very big. Lakhs of people are suffering; lakhs of cattle are being destroyed. At least Rs. 50 crores or so are necessary to tackle the famine on an emergency basis. The State by itself cannot obviously have this amount. So help on a very liberal basis is necessary. I appeal to the Central Government to come out in all possible ways to help the Rajasthan Government so that these problems can be tackled and famine can be tackled on a war footing.

SHRI SANDA NARAYANAPPA (Andhra Pradesh' : Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very glad that the Government has realised, and has created an opportunity both in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha to discuss the drought conditions in the country as well as the flood situation that has affected our food production. All the hon. Members have

expressed concern about the grave situation that has been caused on account of the drought conditions prevailing in the country, in different parts of the States. I come from Andhra Pradesh and I would like to make a few observations and I want to bring to the notice of the Government the existing situation so that Government may immediately make arrangements and take steps not only towards immediate and temporary relief measures but also cause permanent relief measures to be undertaken. Now, Sir, this kind of flood situation in some parts of the country and shortage of rainfall in some other parts have joined together and created an unfortunate situation in the country which we have not been able to tackle in spite of the fact that we have set up a Planning Commission for the last 20 years since independence. We are still only discussing this flood and drought situation in both Houses of Parliament; we have not been able to devise suitable measures to put an end to all these difficulties created by drought and famine conditions in some parts and by flood havoc in other areas. These are the two important things that have to be immediately tackled in order to boost up our food production so that we can stop the import of foodgrains from outside.

On account of this in Andhra Pradesh this year, compared to last year, food production has come down and out of i8r> taluks nearly 174 taluks have been affected. The Deputy Finance Minister visited the Rayalaseema districts like Anantapur etc. last September and he was also convinced that some permanent relief measures are necessary. These areas are chronically suffering areas and immediate relief measures should be extended to them. I know that some temporary relief measures have been undertaken but permanent relief measures have not yet been taken up. In these chronically affected areas in Rayalaseema especially in Anantapur, Cuddappah, Chiltoor and other places, we suggest that the Government should tap tne underground water resources and give an irrigation well lo each ryot so that the famine or the food scarcity situation can be tackled to some extent. This sort of thing has been done to a certain extent but the problem has not been tackled properly. For tapping underground water heavy boring machinery is necessary and 10 to 12 inch boring pipes have to be imported from outside. We find from the statement that foreign exchange for the import of ten rigs has been sanctioned. If we are keen to improve the conditions in these chronically affected areas, if we want to improve the economic conditions of the people there, rural electrification has to be taken up seriously and power should be made available to the areas where wells have been granted.

The Srisailam project in the Krishna river valley is under construction but due to shortage of funds we are not able to complete that project and I would request the Government of India to bestow their attention and sanction the necessary funds to complete that project so that power can be extended at a cheap rate to all the chronically affected areas. Now attention should also be bestowed to dry areas where there is scarcity of rainfall. In such areas for six months in a year the ryots are idle. They are engaged in agricultural operations only for six months. For the remaining six months they have to be provided with some occupation. Some cottage or small-scale industries should be started there so that they get some kind of employment. Only that way their economic condition can be improved. Such cottage or small-scale industries should be developed in these chronically affected areas like Rayalaseema, particularly in Anantapur District.

Then there is the Tungabhadra high level canal. That is the only project that has been completed. One canal has 1o be completed called the Guntak-kal Canal. It has to go to Cuddappah and other areas also. It must be completed and water has to be given to the affected areas so thot they may be benefited immediately. I do hope that the Government while considering this situation in the country will be able to give top priority to such chronically affected areas and complete the prrjects which are under censtruction so that immediate relief can be given to the ryots particularly in the areas where they are really suffering. There are certain areas where people really suffer a lot because of scarcity of drinking water. The Government had already given 20 rigs to Andhra Pradesh and they have dug 120 wells in Anantapur District and out of those 120 wells 110 wells have been successful and the water scarcity in some areas has been remedied to a certain extent. Wherever there is difficulty for drinking water in some other parts, this kind of help must be extended so that the drinking water problem can be completely tackled at

[Shri Sanda Narayanappa] least by the end of the Gandhi Centenary year which we are now celebrating from 2nd October 1968 to 2nd October 196c,. At least by the end of Gandhi Centenary year drinking water should be provided to the rural areas, to every village in the country so that we can divert our attention to tackle other problems like famine, flood and so on. I really thank the Government because they have so far given Rs. 7.50 crores to Andhra Pradesh. The Andhra Pradesh Government have submitted schemes for an estimated expenditure of nearly Rs. 23 crores. The remaining schemes should also be sanctioned and till March the relief works now under Kxecution should be continued in order to provide employment to the people. Foodgrains have also to be supplied to those people where relief works are under execution and I would request the Government of India to look into these matters and give top priority to accord sanction to schemes connected with both temporary measures as well as permanent measures designed to tackle the problems of the chronically affected areas. These are the two things to which I would like to draw the attention of the Government.

In Telangana also some districts have been affected. Similarly the coastal districts like Srikakulam, Vizag, etc. have been affected this year though due to the recent rains in October the situation has improved to a certain extent. We hope that the food position of Andhra will improve somewhat but we can assess the position only by the end of December. Only by then we will be able to get a correct picture of the food position as well as the position of fodder. The Government of India and the Planning Commission should not waste any more time. It is high time that they came together, sit together and formulate schemes on a permanent basis so that hereafter such an unhappy situation may not occur.

5 P.M.

DR. K. RAMIAH (Nominated) : Mr. Vice-Chairman, Sir, a good dea^ of ground has already been covered by the previous speakers and I do not propose to go over it again. The note prepared by the Ministry is very informative but I do not feel happy over it for two reasons. It is a compilation cf the information on the States and the help they need. There is no differentiation made between real drought and slight drought due to either a reduction in total rainfall or a bad distribution of the same. For instance, the damage to crops due to drought may be different in different States and the report does not bring out the seriousness cf the position of drought in Rajasthan as compared to other States.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Further, there is an estimate of the damages in the States the quantum of help required and the help decided on by the Centre as a result of the report by a team of experts sent there by them. Madam, one hon. Member has suggested that no attempt has been made to make realistic estimate of the damages sustained by the different areas. I should like to mention that it is physically impossible to get such a correct estimate because the team sent by the Government of India can only verify the data given by the State by sampling. A more detailed estimate will be time consuming and impossible to undertake.

Now, Madam, drought itself can be of two kinds. For instance, in an area where we get about 40" of rains. Normally a reduction to 20" to 30" in a year or its bad distribution there will be some loss in agricultural production. In Rajasthan however where the actual normal rainfall is only 15", its reduction to 10" will produce more damage than a similar reduction could in another area. The situation in Rajasthan which some of the hon. Members have actually seen is really very bad. The question of lack of funds cannot and should not arise to bring succour and help to this State which is in such a terrible plight.

The second point about the report is that it does not provide any information about the remedial measures which are being taken or are proposed to be taken as a long-range remedy. There cannot be difference of opinion about remedies to be considered. One is a survey of the ground water. For example, in some areas as in Gangetic valley it is easily available while in other areas, such as Rajasthan though we may be able to tap the ground water it may be brackish and may not be suitable for either drinking purposes or for irrigating crops. In still others there ma.y be need for special rigs to tap the ground water. Therefore an immediate step that is to be taken as a long-range measure is to make an intensive survey of the

ground water and utilise it to the maximum extent possible in areas which are periodically subject to drought.

Then, Madam, States which need help when there is damage either due to floods or drought receive grants for relief measures from the Centre. Such grants which amount to some crores of rupees are all spent on relief measures and are not generally utilised for bringing about permanent improvements in the States concerned. For instance, if a State gets a grant of Rs. 10 crores for drought relief there should be some arrangements by which at least Rs. i or 2 crores can be utilised for bringing about permanent remedial measures so that such utilisation spread over a period of years might achieve tangihle results and prevent recurrence of drought to the same extent as it does now.

There is another remedy which is often not thought of, that is, deepening of wells and tanks which are an important source of irrigation in many parts of the country. Most of the irrigation tanks have become silted up and the catchment area which feeds the tanks has become denuded of all vegetation and trees and the water holding capacity of the tanks at present is only a fraction of the original one. This is a problem which has to be intensively taken up in areas where tanks and wells are the main sources of water supply.

Madam, with regard to relief works several suggestions have been made. I think relief works must be such as would not only improve the rural conditions of the area where such works are undertaken but also alleviate the trouble when drought occurs again, say, after two or three years. For instance, in Rajasthan not only a large number of tubewells must be constructed, but the areas where they are situated must be made easily accessible. At present even where tubewells are in position, those are not utilised for lack of power supply. Another idea might be to construct godowns where cheap grains, bajra jowar etc. can be stored safely, particularly in areas periodically subject tc drought. The stores for wheat and ric(may be relegated more to agriculturally favourable areas. Godowns for cheap foodgrains may be particularly valuable in some western areas where famine and drought conditions are of frequent occurrence.

Lastly, I would suggest that the Ministry should set apart sufficient funds to intensify agiicul rural research to evolve drought resistant crops which can be grown in such areas. There is a certain amount of work in progress but there is scope for its intensification. We should determine suitable crops which can thrive under drought conditions and also evolve varieties of such crops which can produce satisfactory yields with limited water supplies. Such research has produced valuable results in parts of U.S.A. and similar work can be profitable in India also, particularly in Rajasthan and western India. This research may play more important part in the activities of the Arid Zone Research Institute in Jodhpur than now.

श्री सी० एल० वर्मा (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति महोदया, पिछले सेशन में जिस वक्त आंध्र के बारे में सूखे का जिक्र हो रहा था उस वक्त मैं हैरान था कि लोग पानी के वास्ते किस तरह से तरस रहे हैं लेकिन आज भंडारी जी और मिर्धा जी और चन्द्र शेखर जी ने राजस्तान के बारे में जो हालत बताई उससे तो समझ में नहीं आता है कि भाई हम वहां क्या इंतजाम कर सकते हैं। यह ठीक है कि हम सुझाव दे सकते हैं कि कुंवें खोदे जांये या फलानी चीज कर दी जाय मगर सब के वास्ते रुपये की भी दरकार है। तो यह सोचने वाली बात है कि आखिर यह सूखापन क्यों होता है और फ्लड्स क्यों आते हैं। इस सिलसिले में कंट्रोल बोर्ड वगैरह बेशक बैठा रखे हैं मगर सूखेपन की जो मेन वजह है वह यह है कि बारिशें नहीं होती और बारिशे क्यों नहीं होतीं इस लिये कि जंगल खत्म कर दिये जाते हैं। सारे हिमालिया में एक कोने से दूसरे कोने को देखिये सब जगह यही हो रहा है कि एक कांट्रैक्टर को कोई ठेका दिया जाता है और उसको सौ पेड़ काटने का ठेका है तो वह हजार पेड़ काटता है और कोई यह नहीं पूछता कि यह कैसे काटा, और कोई यह नहीं देखता कि जो दरख्त काटे गये हैं उनके बजाय कोई और दरख्त लग रहे हैं या नहीं। स्वायल कंजर्वेशन के लिये कुछ रुपया दिया जाता है मगर जहां उसके लिये काम होना चाहिये वहां वह एकदम

[श्री सी० एल० वर्मा]

कम कर दिया जाता है, उसमें कट लग जाता है, जो कट लगाया जाता है वह स्टाफ पर नहीं लगाया जाता, वह तो हमेशा स्कीमों पर ही लगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में 234 रेंजर्स हैं मगर जब कि स्कीमों के लिये रुपया नहीं मिला तो वे सब के सब बेकार हैं, उनके लिये काम नहीं है। तो चाहे वह काश्मीर हो, चाहे दार्जिलिंग हो या हिमाचल हो, सब जगह यही बात है। इसका कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। हर एक स्टेट इसी फिक्र में लगी हुई है कि इस साल का बजट कैसे हो। झगड़ा यहीं आ कर पड़ता है। हमें स्टाफ के टी०ए० या डी०ए० वगैरह के लिये फिक्र है कि कैसे दें। जैसा कि चन्द्र शेखर जी ने कहा कि 12 करोड़ रुपया दिल्ली को सजाने में लगा दिया और जैसा कि 6 करोड़ रुपया चन्डीगढ़ को सजाने में लगता है और वैसे ही हर शहर को सजाने में लगता है मगर कोई यह नहीं सोचता है कि जो देहात में रहते हैं उनका क्या है। 80 फीसदी आबादी देहात के अन्दर है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि देहात को सिवाय पैम्फलेट के, सिवाय इश्तिहारों के, सिवाय लेक्चरों के और क्या चीज मिली है। आपने स्कूल दे दिया है, स्कूल नाम को है लेकिन उसमें क्या टीचर्स हैं? आपने अस्पताल खोल दिया है लेकिन क्या उसमें कोई डाक्टर है? कोई डाक्टर वहां जाता ही नहीं। आपने सेंट्रल हेल्थ स्कीम बना दी है और जितने डाक्टर हैं सब चाहते हैं कि शहरों में रहें। तो शहरों की तरक्की रोजमर्रा हो रही है। इसी वास्ते मैं कहता हूं कि अगर रुपये की इसके लिये दरकार है तो सब से पहले यह सोचना है कि यह रुपया कहां से आना है, किस से बचाना है। उसके बचाव के लिये बहुत कुछ कहा जा सकता है जैसे कि मेरा सुझाव है कि आपके जो ब्लाक्स है उन ब्लाकों से क्या फायदा है सिवाय इसके कि आपने डुप्लीकेशन कायम कर दिया है, एक आपका पंचायत का डिपार्टमेंट है और आपने एक इंस्पेक्टर अपने ब्लाक में भी दे दिया, वह ब्लाक के बी०डी०ओ० के मातहत है और पंचायत का जो डाइरेक्टर वगैरह है उनका अपना अलग कंट्रोल है। एक लाख का बजट है और उसमें से 80 हजार तो तनख्वाह में ही खर्च हो जाता है तो बाकी 20 हजार रुपये में क्या डेवलपमेंट कर सकते है।

सड़कों को देखिये, जैसा कि बार्डर रोड का जिक्र भंडारी जी ने किया वैसे ही उसी तरह से मैं कहता हूं कि अगर सड़कें आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यह काम नहीं चलेगा। इसके अलावा अभी भंडारी जी शिकायत कर रहे थे कि उनके राजस्थान में 74 रु० या 78 रु० क्विंटल से गेहूं मिला मगर मैं तो भंडारी जी की और माननीय मंत्री जी की नोटिस में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में तो हमेशा 115 और 120 रु० क्विंटल मिलता है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : वहां भी 99 रु० हो गया है।

श्री सी० एल० वर्मा : इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट यह हो रहा है कि हम जंगल काट रहे हैं और उसमें खेत बना रहे हैं और गेहूं उसमें बीज रहे हैं। उसका यह नतीजा लाजमी है कि फ्लड भी आयेंगे और आपके यहां स्वायल इरोजन भी होगा। हम कहते हैं कि सैंट्रल गवर्नमेंट सबसिडी दे तो कहते हैं कि सबसिडी देना हमने बन्द कर दिया है। तो जब तक आप इस चीज को रेस्टोर नहीं करेंगे और आप हमको चीपर गेहूं नहीं देंगे यहां के लोग अपने खेतों को बढ़ाने से बाज नहीं आयेंगे और तब आप इन फ्लड्स को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकेंगे।

इसके अलावा जैसी कि हमारी अभी हालत है, चाहे आंध्र को ले लीजिये, मैसूर को ले लीजिये, राजस्थान को ले लीजिये, चाहे वेस्ट बंगाल को ले लीजिये, सब जगह यही हालत है कि रुपया चाहिये और हमारे मोरारजी भाई एकदम कह देंगे कि रुपया नहीं है मगर एक कमिशन जरूर बना देंगे चाहे वह खुशहाली कमिशन हो, फ्लड कमिशन हो या और कुछ हो और उसका रिपोर्ट आ जायेगी जिसमें

सिवाय खर्च होने के और कुछ नहीं होगा। तो इस वास्ते रुपये बचाने के लिये सब से पहले हमें सोचना होगा कि प्रायरिटी किस चीज को देनी है। सब से बड़ी प्रायरिटी पेट की है। अगर पेट में रोटी है, चाहे वह ज्वार की है, चाहे बाजरे की है, आप चुप रह सकते हैं लेकिन अगर पेट में रोटी नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते चाहे एम०ए० कर लें या कुछ कर लें। केरल में सब के सब एम० ए० हैं लेकिन सब के सब भूखे मरते हैं तो फिर एम० ए० करने का क्या फायदा। इसलिये अगर एजुकेशन को कम करना पड़ता है तो आप एजुकेशन को कम करने दीजिये या कोई चीज कम करनी पड़ती है उसको कम करने दीजिये मगर जहां तक पेट की रोटी का सवाल है उसके लिये हमें सब से पहले इंतजाम कर देना चाहिये। बाकी का जो खर्च है उसका खर्च अपने हाथ में है। देखिये ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। चाहे जो स्टेट हो सब अपना कैपिटल बना रहा है, जहां हम जाते हैं वहां देखते हैं कि जहां नई गवर्नमेंट बनी चाहे वह काश्मीर हो या और कुछ हो वहां एक बड़ा सेक्रेटैरियट बन गया है, भोपाल है तो वहां एक बड़ा सेक्रेटैरियट बन गया, लेकिन अगर उतना ही रुपया कहीं हम ट्यूबवेल में लगाते या और चीजों में लगाते तो शायद गरीब आदमी, जो 80 फीसदी आदमी देहात में रहता है वह गरीब आदमी यह महसूस करता कि हमारे लिये कुछ किया जा रहा है। यह सब जगह जो बिल्डिंगों पर रुपया खर्च किया जाता है वह बचाया जा सकता है। कौन सी चीज है जो कि बिल्डिंग के बगैर नहीं कर सकते। तम्बू में लोग रहते हैं, स्कूलों को तम्बू में कर सकते हैं मगर यहां होता यह है कि प्रोडक्शन बाद में होता है पहले बिल्डिंग बनाते हैं। मैं पिछले इतवार को बल्लभगढ़ गया। वहां इंडस्ट्री वालों को लोन दिया है लेकिन उन्होंने वहां इस तरह से प्लानिंग की है कि इस तरह से क्वार्टर बनें, वहां एयर-कंडीशंड प्लांट लगायें, कि सब खर्चा हो गया और कुछ बाकी रहा नहीं। तो आपने तरजीह दी है इंडस्ट्री को। इसके बजाय अगर आप जराअत को तरजीह देते तो शायद हमारी आज यह दशा न होती।

आपने जो यह स्टेटमेंट दिया है इसमें आपने ठीक कहा है कि पंजाब के अन्दर कोई ड्राउट नहीं आया लेकिन उसकी खास वजह यह है कि वहां नहरें हैं और ट्यूबवेल्स हैं और वहां बिजली मिल गई है और इसलिये वहां यह तकलीफ नहीं है मगर आपके स्टेटमेंट में है कि हिमाचल प्रदेश में ड्राउट आया। इसकी खास वजह क्या है, खास वजह यह है कि पानी हमारे पास जरूर है लेकिन वह सब बाहर चला जाता है। हम इतनी लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम देते हैं मगर गवर्नमेंट आफ इंडिया कहती है कि हम इरिगेशन की उन स्कीमों को ही लेने जा रहे हैं जिसमें कि कम से कम इतना एरिया उसके अन्दर आये और वहां सरप्लस हो। इसका नेट रिजल्ट यह है कि हम कभी भी पहाड़ में न तो सरप्लस होंगे और न कभी सेल्फ सफिशियेंट होंगे और नतीजा यह होगा कि हम चिल्लाते रहेंगे और आप यही करते रहेंगे। कोई वजह नहीं है कि जब हमारे पास पानी है तो क्यों नहीं हमारे लिफ्ट इरिगेशन के काम को मंजूर करते। मालूम नहीं कौन सा पैमाना बना रखा है। प्लानिंग कमिशन की बात यह है कि वह मैदान के लिये पैमाना बनाते हैं और उसी को सब जगह के लिये रख देते हैं। हम पहाड़ वाले यह महसूस करते हैं कि प्लान आप देश का, मैदान का बनाते हैं और उसको पहाड़ में लगाते हैं तो वह कैसे हो सकता है। इसी वास्ते सारे पहाड़ के लोग आपसे नाराज हैं चाहे आप दार्जिलिंग को ले लें, चाहे काश्मीर को ले लें, जितनी भी पहाड़ी आबादी है वह बिल्कुल खुश नहीं है। प्लानिंग पहाड़ के नाम पर तो बिल्कुल हुई ही नहीं, वहां के हालात के मुताबिक नहीं हुई। यहां से साइक्लोस्टाइल्ड कापी चली जाती है और उसके मुताबिक करना होता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी है तो वहां के लिये कहा गया कि इस तरह का गुसलखाना बनाओ तब तो पैसा देंगे वरना नहीं देंगे। यह

[श्री सी० एल० वर्मा]

नहीं देखते कि वहां गर्म पानी कहां मिलेगा और अगर उस तरह से वहां का अफसर नहीं बनाता है तो वह अफसर नालायक है क्योंकि जो अफसर खर्च कर सकता है वही अफसर लायक है, जो कम खर्च करे वह लायक नहीं है। तो फिर उसको वह बनायेगा ही चाहे वह फिर काम में आये या न आये, चाहे वह लकड़ी रखने के काम में ही आ जाय मगर वह गुसलखाने के काम में नहीं आता है। तो यह हमारी प्लानिंग है।

तो जो हमारी लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम है उसके लिये मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वह काश्मीर हो मगर जहां पानी है वहां लिफ्ट इरिगेशन जरूर हो जानी चाहिये। इसके अलावा जैसे कि आंध्र प्रदेश है या राजस्थान है जहां कि सूखे टैक्स बन सकते हैं और लोग उसके लिये लाखों सैकड़ों की संख्या में काम करने को तैयार हैं तो क्यों नहीं हम टैंक्स बनाते जिससे कि उसमें बरसात का पानी जमा हो जाय ताकि जो ये मवेशी हैं जो कि हमारी बेवकूफी की वजह से हमें कर्स कर रहे हैं वे तो बच जाएंगे। अगर हम उससे इरिगेशन नहीं कर सकेंगे तो कम से कम उन मवेशियों के लिये पीने का पानी तो हो जायगा।

स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है यह आजकल हर एक स्टेट गवर्नमेंट कहती है लेकिन वह यह जरूर चाहती है कि हमारे पास पावर हो, चाहे वह मद्रास हो, चाहे वह केरल हो, सब पावर मांगते हैं, लेकिन पैसा उनके पास है नहीं तो पावर का क्या होगा। इस लिये उन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सोच लेना चाहिये कि उनको जो पावर लेनी है उसको वह पूरा भी कर सकते हैं या नहीं, उसका वह इस्तेमाल भी कर सकते हैं या नहीं, उससे आमदनी भी कर सकते हैं या नहीं वरना इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि यह शहरों के लिये जो सोचना है इसको बन्द कर दिया जाय और अगर हो सकता है तो जो सो-काल्ड वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको आप बन्द कर दें क्योंकि वेलफेयर सब से बड़ा पेट का है, अगर पेट का वेलफेयर हो जाता है तो बाकी चीजों का हो जायेगा और अगर पेट का वेलफेयर नहीं है तो बाकी चीजों का वेलफेयर करने से कोई फायदा नहीं है और न इससे लोगों की बेचैनी दूर हो सकती है, यही मेरा कहना है।

जहां तक फ्लड्स का सवाल है, मैं हैरान हूं कि बिहार के बारे में आपने पेज 19 में लिखा है कि बिहार में एक सेंट्रल इनवेस्टिगेशन टीम गई थी 18 नवम्बर को और आपने यह स्टेटमेन्ट रखा है हाउस में और 10 अक्तूबर को वहां पर, चूंकि इस वक्त बिहार में राष्ट्रपति का राज है, मीटिंग हुई थी होम मिनिस्ट्री की तरफ से। उसमें सारे फ्लड्स का जिक्र आया, सब कुछ वहां पर कहा गया। बहुत सी बातें उनकी नोटिस में आईं मगर अफसोस यह है कि 18 नवम्बर तक आपके उस सेन्ट्रल स्कीम की रिपोर्ट नहीं आई। अगर यह हालत हमारे राष्ट्रपति राज की है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है तो फिर क्या हो सकता है। हम तो अपने साथ खुद ही ज्यादती कर रहे हैं, हम अपना इंतजाम खुद नहीं कर सकते, हमारा अपना प्रबन्ध कोई है नहीं। हालांकि 10 अक्तूबर को सारा फैसला होता है उसके बावजूद भी जब कि कुछ करना नहीं था सिर्फ उस टीम का लिखना था स्टनोग्राफर को डिक्टेट करके, मगर वह डिक्टेट भी नहीं कर सके 18 नवम्बर तक। खास तौर से बिहार जहां से फूड मिनिस्टर खुद आते हैं। जब बिहार का ऐसा हाल है, तो राजस्थान का क्या हो सकता है।

(Time bell rings.)

इस वास्ते मैं निवेदन कर रहा था कि अगर इस चीज को खत्म करना है तो पहला आपका काम है साइल कन्जर्वेशन का। पहाड़ों में और हिमालय के अंचल में खास तौर पर दरख्तों की कटाई हो रही है और नये दरख्त नहीं लगाये जा रहे हैं। वैसे ही

बंगाल में दार्जिलिंग का हाल है। पहले जो टी गार्डन ओनर्स थे वह युरोपियन थे उन्होंने गार्डन्स बेच दिये अब उन टी गार्डन्स की हालत बहुत खराब है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है साइल कन्जर्वेशन को ज्यादा नज़दीक से देखें और जो दूसरे वेलफेअर की स्कीमें हैं उनको पूरा कर दें जिससे ोगों के रोज़गार के लिये कुछ न कुछ इंतजाम हो जाय।

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्थान) : उपसभापति महोदया, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बाद बोलने वाला कोई नहीं होगा और मैं सबसे आ ीर में बोल रहा हूं।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : क्यों, आपके बाद क्यों नहीं है।

श्री कुम्भाराम आर्य : क्योंकि समय संकेत कर रहा है। साढ़े पांच बजे के बाद ोई बोल नहीं सकेगा। सब बोल गये इसलिये मेरा ोलना भी बहुत कम होगा क्योंक जितनी बातें . . .

श्री राजनारायण : मैडम, जवाब कल हो सकता है।

श्री महावीर प्रसाद भार्गव (उत्तर प्रदेश) : आज ही होगा।

श्री कुम्भाराम आर्य : मेरा समय मत लीजिए। पहले मिला ही कम है, जितना मिला है उसमें बाधा होगी।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की हालत बड़ी गंभीर है, वह अकेली इसलिये गंभीर नहीं है कि वहां अकाल काल संकट का कारण बना हुआ है, वहां अकाल के साथ दूसरा सकट भी बना हुआ है, अकाल के अंदर दूसरी भारी चिंता वहां बढ़ी हुई है। वहां की तात्कालिक स्थिति बतलाती है कि संकट बड़ा गंभीर है। अकाल के बारे में राजस्थान में एक किंवदंती है जिसको राजस्थान का एक एक आदमी जानता है और वह हर आदमी बता सकता है, जो इस प्रकार है :

"पग पुगल धड़ मेडते
बाहु जै बाहड़ मेर ।।
घिरतो फिरतों जोधपुर ।
ठावो जे बीकानेर ।।

अकाल का यह क्षेत्र है, जिसके अंदर यह चौबीस घंटे विराजित रहता है, इसके अंदर कभी परिवर्तन नहीं आया। यह आजादी स पहले से चली आ रही स्थिति है। आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद जब से जनता के प्रतिनिधियों की सरकार बनी है उसका दृष्टिकोण अकाल के प्रति सहानुभूति का न रहकर राजनैतिक रहा है। इसकी वजह से एक तो सरकार का कहर और दूसरा अकाल, दो संकट वहां की जनता के ऊपर आ गिरे। आज वहां का एक एक आदमी कहता है :—

"भलां नरां घर भूख। चौरां रे घर चूरमो ।।
चतर जण री चूक। चांढ़ै दीखै चतरिया ।।"

अर्थात्, जो ईमानदार लोग हैं वे कमाई करके अपने दिन निकालना चाहते हैं, अपने पैर पर खड़े रहना चाहते हैं, उन लोगों को मजबूर किया जाता है कि वे मांगने लगें जिसके लिए वे लोग तैयार नहीं हैं। आज उनकी यह स्थिति सरकार ने राजस्थान में बना रखी है।

कहने के लिये काम शुरू है और लोगों को राहत भी पहुंचायी जा रही है लेकिन मैं सरकार के पत्रों के जरिये यह कह सकता हूं कि वहां 12-10-68 तक केवल 7 काम शुरू किये गये थे और वे 7 काम जो शुरू किये थे उनमें 5 काम खाली जैसलमेर में थे और 2 काम बीकानेर के अंदर थे, कुल 41,000 लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे। इसके साथ राजस्थान सरकार की रिपोर्ट यह कह रही है कि अकाल 27,000 गांवों को प्रभावित कर चुका है और 15 लाख आदमी इससे प्रभावित होकर काम के लिये आयेंगे उनको काम देना पड़ेगा। इससे आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, और समझ सकते है कि यह काम किस

[श्री कुम्भाराम आर्य]

तरह से किनारे लग सकेगा ? मैं तो यह देख रहा हूं कि सरकार की सुनियोजित योजना जिस कामयाबी के साथ फेल होती जा रही है उसी कामयाबी के साथ अकाल जनता के लिये एक भयंकर रूप धारण करके सामने आ रहा है। आज राजस्थान का पशु मर गया, मरता जा रहा है और शेष मर जायेगा। राजस्थान के अंदर सरकार, पांच, सात और दस लाख से ज्यादा पशु नहीं बचा सकेगी, पचास और 60 लाख पशु धन इस अकाल के गाल में चला जायेगा, इस पशु धन को बचाने का कोई रास्ता आज के दिन नहीं। मैं चाहूंगा भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों इस तरफ ध्यान दें। राजस्थान की तरफ भारत सरकार का जितना ध्यान जाना चाहिये नहीं गया है। बतलाने के लिये कुछ काम किये जाते हैं। भारत सरकार ने पहले एक दल भेजा जो जांच के लिये गया। दल ने पूरे राजस्थान का दौरा तीन दिन के अन्दर खत्म कर दिया, जब दल को पूरी स्थिति देखने के लिये कहा गया तो उन्होंने कहा हमको रिपोर्ट देने की बहुत जल्दी है क्योंकि कहत की स्थिति भयंकर है इसलिये हम ज्यादा समय नहीं लगा सकते। तीन दिन में जो देखा समझा है उसी से सब मिल गया। राजस्थान की रिपोर्ट दे देंगे। यहां आने के बाद वह रिपोर्ट एक महीने तक संबंधित मंत्री तक नहीं पहुंची, या तो रिपोर्ट लिखी नहीं गई या फिर विषय इतना बड़ा था, जिसकी कहानी इतनी बड़ी हो गई कि उनको लिखते लिखते इतना समय लग गया। यह हालात बतलाते हैं कि राजस्थान की जनता को भारत सरकार और राजस्थान की सरकार बचा नहीं सकती। सबसे अच्छा, सबसे सुंदर तरीका यह है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार को एक ऐलान कर देना चाहिये कि राजस्थान की जनता अपनी जिंदगी के लिये खुद जिम्मेदार है, जहां जाना चाहे चली जाय, ऐसा ऐलान हो जाय तो कम से कम दो पैर वाले तो अपनी जान बचा लें। लेकिन सरकार की ओर से जो रोजाना भाषण दिये जाते हैं और आश्वासन दिये जाते हैं उन भाषणों और आश्वासनों की वजह से जो जनता को धोका होता है उस धोके की वजह से लोगों को मरना पड़ता है। जब मर जाते हैं तब सरकार कहती हैं अनाज की वजह से नहीं मरे हैं मौत की वजह से मरे हैं। मैं सरकारी पक्ष से पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में बिना बीमारी के भी कोई मरता है क्या ? बिना बीमारी के अगर कोई मरता हो तो यह उत्तर राजस्थान के लिये ठीक है लेकिन मरते सब बीमारी से हैं। आखिर बीमारी क्यों पैदा होती है यह देखने की बात है। खाने के लिये अनाज नहीं मिलता, उधर उनको मजदूरी करने के लिये विवश होना पड़ता है इसलिये बीमार होते हैं। श्री कौलायत के अंदर 22 आदमी मर गए हैं जिसको न राजस्थान सरकार मानती है और न भारत सरकार मानने का हौसला कर सकती है जब कि मस्टर रोल के अंदर उनके नाम लिखे हुए हैं और 22 दिन तक उनको पेमेन्ट नहीं किया गया। इसके बाद यह कह देना कि उनको तो कोई डिजीज हो गई थी। डिज़ीज तो पैदा होती ही है इसलिये कि खुराक नहीं मिलती और सरदी के अंदर जो ठिठुरते हैं, सवेरे उनको मिट्टी होने के लिये खड़ा होना पड़ता है। उत्तर देने वाले मिनिस्टरों को उस हालत में तीस दिन खड़ा कर दिया जाय तो एक नहीं जी सकता। लेकिन राजस्थान के लोगों से अपेक्षा की जाती है वे 22 दिन भूखे रह कर बिना मजदूरी 'पगार' के काम करके भी जिंदा रहने के जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी को वहन नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ देखना पड़ेगा। राजस्थान में जितने काम होते हैं वे सब राजनैतिक दृष्टिकोण से ही किये जाते हैं। जोधपुर जिले के अंदर वर्षा की औसत का 66 परसेन्ट के आसपास वर्षा हुई, इतनी वर्षा जयपुर जिले के अंदर हुई। जोधपुर अकालग्रस्त घोषित हो गया और जयपुर अकालग्रस्त घोषित नहीं हुआ क्योंकि वहां से

काग्रस जात कर नहा आइ, जोधपुर से जीत कर आई। यह नजरिया एक दोहरी मार करता है। अगस्त तक के महीने की सरकार की रिपोर्ट है कि उदयपुर जिले की हालत संतोषजनक है और सितम्बर में एकदम से कहत खड़ा हो जाता है। टोंक जिसकी शुरू से यह रिपोर्ट है कि हालत खराब है, उसे आज तक स्केयरसिटी एरिया घोषित नहीं किया गया। क्योंकि टोंक में से एक भी कांग्रेस का आदमी जीत कर नहीं आया, केवल एक मिनिस्टर दो जगह से जीत कर आया। इसलिये पक्षपात का दृष्टिकोण है। इतना ही नहीं, राजस्थान के लोगों को मजदूरी बहुत देर से मिलती है। मेरे मित्र कह रहे थे कि 7 दिन में देने का फैसला किया हुआ है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 7 दिन का फैसला नहीं है बल्कि सरकार का फैसला 15 दिन का है। यह फैसला बुद्धिसंगत नहीं है, व्यवहार संगत भी नहीं है। इस तरह का फैसला देकर भी सरकार अभिनन्दन चाहती है। अगर किसी कांग्रेसी सदस्य को दुबारा टिकट लेना होगा तो वह ऐसा करेगा लेकिन कोई ईमानदार आदमी धन्यवाद देने के लिए अपने ईमान को नहीं बेचेगा। मजदूरों को मजदूरी जल्दी मिलनी चाहिये। उनको इस समय जो मजदूरी मिल रही है वह कम मिल रही है, उनको पूरी मजदूरी मिलनी चाहिये।

अभी जब कृषि मंत्री जी वहां गये थे तो उनके सामने सवाल पैदा हुआ कि लोगों को मजदूरी कम मिल रही है। तब राजस्थान सरकार ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया। राजस्थान सरकार ने कहा कि एक आदमी जो बालिग कहलाता है उसको 1 रुपया 12 आना मिलता था, अब उसकी जगह पर 1 रुपया 50 पैसा कर दिया गया है। इस तरह से वहां पर यह मजदूरी बढ़ी। इस तरह का काम करके सरकार कहती है कि हम जनता को बचाने में कामयाब हो जायेंगे। हम कहते हैं कि वह कभी भी इस तरह से कामयाब नहीं हो सकती है।

सरकार कहती है कि इस काम के लिए 61 करोड़ रुपया चाहिये, अगर भारत सरकार त्रैमासिक नहीं देती है तो इस संकट से निकलने में असमर्थ है। भारत सरकार की रिपोर्ट तो यह कहती है कि 9 करोड़ रुपये से काम चला लो। वह 9 करोड़ रुपया दे देगी। सवाल यह आता है कि 52 करोड़ रुपया कहां से आयेगा? क्योंकि राजस्थान सरकार को इतना रुपया लाने की हैसियत नहीं है। राजस्थान की सरकार 52 करोड़ रुपया नहीं ला सकती और न वहां की जनता को बचा सकती है। इतना रुपया लाने की उसकी हैसियत नहीं है। यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इतने रुपये का इंतजाम करे।

इतना ही नहीं, एक खतरा और है, और वह खतरा यह है कि जो हालात आज राजस्थान के हैं, जिस तरह से लोगों को महंगा अनाज और कम अनाज दिया जाता है, देर से उनको पैसा दिया जाता है, ऐसी स्थिति के अन्दर लोग कमजोर होंगे, उनमें बीमारी पैदा हो जायेगी। इस समय सरकार उनकी हालत की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जब बीमारी फैल जायेगी, लोग मरने लग जायेंगे तब सरकार स्टेटमेंट देगी कि यह ईश्वर के अधीन बात थी। एक बीमारी फैल गई जिससे हम लोगों को बचा नहीं सके। मैं हाउस के अन्दर कहना चाहता हूं कि ऐसे हालात के अन्दर बीमारी जरूर आयेगी। जिस हालत में सरकार वहां के लोगों के साथ व्यवहार कर रही है उससे लाखों आदमियों के मरने की नौबत पहुंच जायेगी। भारत सरकार को अभी से इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

भारत सरकार ने मांग करने पर रेल किराये में छूट देने का आदेश दिया। वह हुक्म चला, बहुत सुन्दर चला, बड़ा अच्छा हुक्म निकला। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इस हुक्म में भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि हम किराये में तो कमी कर देंगे जो अपने मवेशियों को बाहर ले जायेंगे। लेकिन

[श्री कुम्भाराम आर्य]

यह किराया तब ही कम किया जायेगा जब इस बारे में कमिशनर सर्टिफिकेट देगा। सरकार को यह पता नहीं कि बाड़मेर कमिशनर के हैडक्वार्टर्स से करीब 300 और 350 मील की दूरी पर है। एक किसान 350 मील तक सर्टिफिकेट लेने आयेगा और इतने ही मील वापस जायेगा तो सरकार उसको जो किराये में रियायत देने वाली है वह उसका रेल के किराये में सर्टिफिकेट को लेने में ही लग जायेगा। इस तरह के आदेश का वह कैसे लाभ ले सकता है? इस तरह का विवेकहीन आदेश जारी करके सरकार कहती है कि हमने सब इंतजाम कर दिया। इंतजाम जनता के मरने का तो कर दिया लेकिन बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए यह बड़ा जरूरी है कि कुछ बचाने के तरफ भी ध्यान देना चाहिये। अगर भारत सरकार का ध्यान बचाने की तरफ नहीं गया तो राजस्थान के लोग मर जायेंगे।

अकाल के स्थायी हल के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका केवल एक ही हल है और वह है राजस्थान नहर को जो पहले कान्डला तक रखी गई थी उसे कान्डला तक पहुंचाया जाय ताकि बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और बीकानेर जिलों में, जहां 24 घंटों अकाल रहता है, सदियों से रहता है, उसको दबा सके। इसके सिवाय और कोई जरिया नहीं है।

राज्य सरकार के ऊपर इस तरह का बोझा नहीं डाला जाना चाहिये। वह इतना पैसा नहीं लगा सकती। राजस्थान सरकार तो उतना ही पैसा लगा सकेगी जितना भारत सरकार देगी। यह एक राष्ट्रीय समस्या है, उसको भारत सरकार को हाथ में लेना चाहिये। भारत सरकार इसको हाथ में नहीं लेती है तो फिर वहां की जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिये। वहां की जनता को साफ कह देना चाहिये कि जब भी अकाल पड़ता दिखलाई दे तो भाग जाना चाहिये, कोई सरकार के भरोसे पर रहेगा तो मर जायगा। कुवें बनाने, ट्यूबवैल लगाने से समस्या का हल नहीं होगा क्योंकि वहां पर पानी 350 फुट तक नीचे मिलता है वह भी कहीं खारी कहीं जहरीला मिलता है। अगर पी लिया जाय तो मर जाना पड़े और अगर हाथ लगा लिया जाय तो चमड़ी फट जाये। इस तरह के हालात में वहां के लोगों को जिन्दा नहीं रखा जा सकता और न वहां के लोग इस तरह के पानी से जिन्दा रह सकते हैं। वहां के लोगो को जिन्दा रखने का एक ही जरिया है राजस्थान कैनाल को पूरा किया जाय। दूसरा काम गंगानगर जिले में जितने सिंचाई के सिस्टम हैं, चाहे वह राजस्थान कैनाल हो, चाहे सरहिन्द कैनाल हो, चाहे गंगा कैनाल और चाहे भाखडा कैनाल हो, सबके अन्दर पूरा पानी देना चाहिये। गंगानगर का जो सिंचाई क्षेत्र है वह अकाल स्थिति में पहुंच गया है। वहां का किसान 15 प्रतिशत खेती नहीं कर सकता है। आज भी वहां की नहरें बंद हैं जबकि बिजाई के दिन हैं। किसान अपना हल बैल घर में लिए बैठा है और खेत सूखे पड़े हुए हैं क्योंकि नहरों में पानी नहीं आ रहा है। सरकार नींद ले रही है इसलिए नहरें भी नींद ले रही हैं। अगर ये दोनों नींद लेते रहेंगे तो देश उजड़ेगा, बसेगा नहीं। इन हालात पर कांग्रेस की ओर से भी नाराजगी प्रकट की जाती है और कहा जाता है कि सरकार के पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह उस काम को पूरा कर सके। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि राम और राज्य से कोई बड़ा नहीं है। सवाल क्षमता का नहीं, सवाल मन का है, ईमानदारी का है। अभी तक सरकार ईमानदारी के साथ 80 प्रतिशत गांव में जो जनता रहने वाली है उसके प्रति निष्ठावान नहीं। इस निष्ठा के अभाव की वजह से आज गांव का आदमी दुखी है, दुखी ही नहीं अकाल जैसे संकटों में बेमौत मर रहा है। सरकार उन लोगों के लिए निष्ठावान है जो एक्सप्लाइट करने वाले हैं, जो बिचौलिये होते हैं, जिनका एक हाथ आगे और दूसरा पीछे रहता है।

उनका यह काम रहता है कि आधा हमारा और आधा सरकार का । हमारे यहां कहावत है "आधा देवी देवता, आधा क्षेत्रपाल" । इस तरह का राज्य न कभी आया और न कभी आयेगा ।

मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार--राज्य सरकार--जो पक्षपात की नीति बरत रही है, उसके अन्दर हस्तक्षेप क्यों नहीं करती ? जालौर जिले को पैसा ठीक तरह से नहीं मिल रहा है। जालौर जिले को 25 हजार रुपया देने की बात है और जैसलमेर जिले में दो लाख रुपये देने की बात है। जैसलमैर जिले के अन्दर 1 लाख 40 हजार आदमी हैं और जालौर के अन्दर 5 या 6 लाख आदमी हैं। 5 या 6 लाख आदमियों के लिए तो 25 हजार और जैसलमैर जिले को, जहां 1 लाख 40 हजार आदमी रहते हैं, दो लाख। इस तरह का पक्षपात ।

आज जहां भी काम खुल रहे हैं वहां कागज पर ही खुल रहे हैं। स्कीमें जो भी घोषित की जा रही हैं वे भाषण देने के लिए ही घोषित की जा रही हैं, लोगों को काम देने के लिए नहीं। लोगों को धोखा देने के लिए घोषणायें की जा रही हैं। मजदूर मजदूरी करने के लिये जाता है तो उसका नाम मस्टर रौल पर नहीं लिखा जाता उसकी मजदूरी नहीं लगाई जाती। राजस्थान का किसान मजदूर इस भयंकर संकट में फंसा है, लेकिन भारत सरकार आँखें बंद कर किये बैठी है । राजस्थान की जनता कब तक सरकार की आस लगाये रहेगी ? उसे फैसला करना होगा कि उसे जीने के लिए क्या करना है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि राजस्थान के लोग हाथ फैलाना नहीं जानते हैं, भीख मांग कर जीने के स्थान पर मरना पसंद करते हैं। यह उनकी आदत है। यह उनकी सभ्यता है, संस्कृति है । अगर सरकार इसी तरह से चलती रहेगी तो वहां की जनता को सोचना पड़ेगा कि अकाल और सरकार, दोनों से किस तरह से निपटा जाय । इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री चन्द्र शेखर : जब आप मिनिस्टर थे तो आप क्या कर रहे थे ?

श्री कुम्भाराम आर्य : मेरे गले में बहुमत का फांस लगा रखा था। मैं बहुमत में नहीं था। कांग्रेस ठीक होती तो मैं छोड़कर क्यों आता ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : Minister !

श्री राजनारायण : माननीया, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और जब मंत्री जवाब दें तो वे उनका जवाब दे दें ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Rajnarain, I have got 4 or 5 names more but it was announced that the Minister would reply at 5.30 P. M.

श्री राजनारायण : मेरे सुझाव इस प्रकार से हैं । एक तो सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्रत्येक गांव पंचायत में एक हजार आबादी पर एक सस्ते गले की दुकान खोली जाय । दूसरे, भूमिहीन और बकार लोगों के लिए लंगर खोला जाय जहां पर उन्हें मुफ्त भोजन दिया जाय । गरम कपड़ों का व्यापक प्रबन्ध हो । टैस्ट वर्क बड़े पैमाने पर खोले जायें। दो रुपया प्रतिदिन से मजदूरी कम किसी को न दी जाय जो मिनिमम वेज कानून में निहित है । दवाई की व्यवस्था हो । चारे की व्यवस्था हो । बच्चों की फीस माफ हो । सहायता और अनुदान उदारता के साथ दिया जाय । जो कर्जा लेना चाहें उन्हें बिना सूद के कर्जा दिया जाय । सूखे के कारण जो पशु मर गये हैं उनके लिए मुआवजा दिया जाय । सीमा क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्रियात्मक कदम उठाये जायं । (*Interruptions.*)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Shri Rajnarain, that will do.

श्री राजनारायण : माननीया, राष्ट्रपति जी का जो पत्र आया है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं । (*Interruptions.*)

[श्री राजनारायण]

आप का दिनांक 8 सितम्बर का पत्र प्राप्त हुआ। उस के लिए उन की ओर से धन्यवाद है। जिन दो विषयों के बारे में आप ने लिखा है उन के संबध में संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी को सितम्बर में जो पत्र मैं ने लिखा था उसका जवाब भी मंत्री जी दें क्योंकि वह खत उनके पास है।

THE DEPUTY CHAIRMAN : That will do. You had said that you would read out only suggestions. No more. The Minister will reply.

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपकी पार्टी भी वहां विरोध कर रही है।

श्री राजनारायण : हमारी पार्टी वहां विरोध कर रही है तुम्हारी सोना पचाने वालों का।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I consider that we had a very important debate on one of the very important topical issues before our country. I am thankful to the hon. House and to all the hon. Members who have participated in this debate.

श्री राजनारायण : असल में शिन्दे साहब आप तो न्याय करते उस समय जब आप कल जवाब देते। कल हम लोग 5 से 6 बजे तक बैठे इसके लिये।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I have to pilot a Bill in the Lok Sabha tomorrow. At the outset I wish to assure Members that all the reasonable suggestions made by them will receive due consideration from the Government and some of the suggestions will be passed on to the Rajas-than Government for their action. Unfortunately the current year has been a year of calamities. This year we had cyclones in certain areas, then there were calamities like floods where valuable human lives were lost and in August the situation was rather very disturbing because at that time many of us were afraid that the drought situation may develop in many parts of our country. At that time the rainfall was deficient in Andhra, Mysore, South Maharashtra, Orissa and a number of other areas including Rajasthan but fortunately for us in September/October large parts of our country received good rainfall and as a result of that in many parts of our country the situation has considerably improved. Many Members have expressed concern whether as a result of severe drought situation prevalent in Rajasthan, the situation would go out of our control. May I express that though the situation in Rajasthan is difficult the Government feels confident that the situation will remain under control and we shall be in a position to handle the situation with confidence. As far as the food problem is concerned—because drought immediately affects human beings and in Rajasthan has considerably affected the cattle wealth also and I will come to that later—the drought situation as and when it affects large tracts of the country, it immediately affects the availability of food and even the price-line is affected adveisely but this year by and large, all over the country, the price* line has been behaving very well and in fact there are reports from certain parts of the country that the prices are falling down. Even in the case of Rajasthan some Members have expressed a fear that the prices are going up. May I submit . . .

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI Are these prices at the official level ?

SHRI ANNASAHEB SHINDE : May I submit for the information of the House that there was some upward trend in September-October. For instance wheat prices . . .

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : You are giving the market prices.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I am coming to that. I am covering that point. I know that you have raised that and I would meet that. Regarding wheat even the price-level in Rajasthan is being maintained at a reasonable level and this is because the State Government as well as the Government of India are taking due precautions to see that reasonable quantities of food are made available to Rajasthan, I was referring to wheat prices. By June end the prices were ranging between Rs. 63 and Rs. 73 but in September-October the prices went up and were ranging between Rs. 85 and 104. By November end the prices have been ranging from Rs. 86 to ioo. Again the case of jowar in September-October the prices were between Rs. 82 and R?. 84 but in November the price? have been ranging between R?. 59 and Rs. 72. The same is the case with Bajra. In September-October

prices went up to Rs. 70 to Rs. 95 but again in November the prices are round about Rs. 74. Regarding barley in September-October the prices were between Rs. 65 and Rs. 70 and in November it is between Rs. 63 and Rs. 73.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : They must be Kotah district prices.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : These are prices reported from various parts of Rajasthan.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : One of the centres must be Kotah.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I was mentioning this in order to dispel any fear in the minds of Members whether the food s'tuation in Rajasthan is likely to cause any anxiety to us. We are making reasonable supplies to the Rajasthan Government and in the future .

श्री राजनारायण : रीजनेबिल माने क्या । कितना आप दे रहे हैं ।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Last month we allotted 35,000 tonnes as against 10,000 to 15,000 tonnes that we were supplying a few months earlier. I quoted this figure for November. For December we have allotted 45,000 tonnes to Rajasthan. As a result of this the food situation is not at all alarming. It is completely under control and this view was expressed by the Chief Minister of Rajasthan when the central team which visited Rajasthan had occasion to discuss with him.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: How much will it be increased from the eight kilos they are getting ?

SHRI ANNASAHEB SHINDE : What should be the quantum in particular areas is entirely at the discretion of the Rajasthan Government. We do not come in their way. How many fair price shops should be opened, how the distribution should be arranged, all these are matters subject to the decision of the Rajasthan Government. We are concerned with making bulk supplies to the Rajasthan Government and as far as that is concerned, I am quite sure that we should be in a position to maintain reasonable suppplies to Rajasthan. Shri Rajnarain was worried about what I meant by reasonable supplies. Even during the Bihar drought there was a controversy as to what should be the reasonable quantity and he never accepted our point that the particular quantum would meet the reasonable requirements of Bihar but ultimately whatever was supplied to Bihar during that period helped us to keep the situation completely under control and helped us to overcome the drought period in Bihar. On similar lines, hon. Members need not have fear that the food situation in Rajasthan would go out of our control and we shall be in a position to make reasonable supplies in time to come up to June or the next monsoon.

श्री राजनारायण : एक जैल का कैदी जितना खाता है उतना आप दे सकते हैं ।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : The hon. Member should not interrput me at every point. He can raise questions later.

THE DEPUTY CHAIRMAN : There is no need to interrupt.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : If he puts some questions, I will answer him laterbut let him not disturb now.

श्री राजनारायण : इंटरप्शन यह नहीं कहा जाता । इस को कभी इंटरप्शन नहीं कह सकते । हमारा क्लैरिफिकेशन है कि एक आदमी को कितने छटांक आप देना चाहते हैं । कितना एमाउन्ट है ? राज्य सरकार से पूछा है कि वहां पर एक आदमी को पूरा खाना देने के लिये कितना गल्ला चाहिये ? यह हम जानना चाहते हैं । यह कोई इंटरप्शन है ?

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Shri Chandra Shekhar, one of the Members of this House, who has, along with some other colleagues, been good enough to visit the drought areas of Rajasthan made a number of critical remarks. In regard to some points I would touch some of them but he has raised one of the very important points that the morale of the people in Rajasthan is excellent. I think this is a very imporant point and he has rightly read the situation in Rajasthan because after whatever the State Government may do or the Centre may do, unless the morale of the people is high it is never easy to meet the situation and with the high morale of the people it should be possible for us to overcome the difficult period that lies ahead during the next few months. A number of hon. Members have referred to the point that deaths have taken place or are taking place as a

[Shri Annasaheb Shinde]

result of starvation arising out of the severe drought conditions prevailing in Rajasthan. We have been trying to find out from the Rajasthan Government whether any such deaths have taken place. And we have been assured by the Rajasthan Government that no such deaths have taken place so far. I think hon. Members should not disbelieve the State Governments. Hon. Members are aware that in the year 1966-67, when the drought situation was prevailing in U.P., Bihar and Madhya Pradesh, a countless number of reports of deaths appeared in the press. And even from very responsible social workers important statements about starvation deaths emanated. Yet, even when the the non-Congress Governments were in power in many of these States, not a single report of starvation death was corroborated by them. I can understand hon. Members' anxiety; I share their anxiety.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : They also depend upon the medical authorities, upon what they say ,

SHRI ANNASAHEB SHINDE 1 But they should not ordinarily disbelieve a State Government. And as far as the current situation is concerned, I see no reason whatsoever to disbelieve the reports submitted by the State Governments about starvation deaths.

श्री राजनारायण : देखिये, फिर आप कहेंगे शिन्दे साहब कि आप को टोका जा रहा है। मेजा तहसील की रपट है कि जिस दिन वह आदमी मरा उसके घर में थोड़ा दाना था। क्या आप कहेंगे कि यह रपट गलत है ?

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I will refer this case to the Rajasthan Government again if the hon. Member wants it.

Then again a statement was made that a large number of cattle are migrating to Pakistan.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Not large.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : May not be large but statements are being made on the floor of this House again and again that the cattle are migrating to Pakistan. To the best of the information available with the Rajasthan Government no such report has come to their notice and the reports appear not to be correct.

Madam, always the point is made in such debates by hon. Members that permanent measures, or measures which would provide permanent protection to drought areas are not being taken either by the Centre, or the State Governments. I wish to dispel this impression with all the strength at my command. And may I give just one example, Madam Deputy Chairman? I have a list with me now of 34 major irrigation projects which have been taken up in this country. Some of them have been almost completed and some of them are about to be completed and they help in providing water to the drought affected areas, or areas which are subject to recurrent droughts, and the total cost of those projects comes to almost Rs. 800 crores. I can understand the concern of the hon. Members that the Rajasthan canal should be expeditiously completed but at the same time hon. Members should appreciate that the Rajasthan canal also is one of the projects, which has been planned in order to provide protection to the very different drought affected areas or those subject to recurrent droughts. So all over the country large areas are now being covered, or are likely to be covered in the near future by the major irrigation system. I, Madam Deputy Chairman, come from an area which subject to recurrent droughts, and in my own district a number of major irrigation projects have been taken up. Some of them have been completed, and these irrigation projects have provided very substantial relief to the drought-affected areas. What is true in the case of my district is true in regard to many parts of our country.

Then, Madam Deputy Chairman, at the same time soil conservation measures are going on and it is because in some areas the rainfall is scanty. So soil conservation is a very important measure undertaken, and now millions of acres have been brought under soil conservation works.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I can give all that figure. I do not have the exact figure with me presently, but I will be in a position to give that figure.

श्री राजनारायण : कितना है ? हम को मालूम हो।

श्री राजनारायण : 2 करोड़ एकड़ की योजना थी और 11 लाख एकड़ में हुआ है।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : No, no, your information is completely wrong. As far as the Third Plan is concerned, almost the targets have been completed. There was no shortfall as far as the Third Five Year Plan was concerned. Almost the targets have been completed. Then there are the afforestation schemes and minor irrigation schemes. For instance, take the minor irrigation schemes. During the last three years we have been giving to States about Rs. too crores per year for executing minor irrigation works. Apart from that, during the last few years we have been insisting on institutional financing agencies to provide finance to execute minor irrigation works . . .

SHRI LOKANATH MISRA : But that is being washed away in the ocean.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : . . . and hon. Members will be satisfied to know that the institutional finance to the tune of . . .

श्री राजनारायण : जाने दीजिये, रुपया ले कर हम क्या करेंगे। इतना रुपया तो प्रधान मंत्री पर खर्च हो जाता है।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : . . almost Rs. 120 crores is likely to be provided during the current year, and during the coming years this figure is likel> to increase more and more. Then in regard to pump sets, for instance, up to the year 1960-61 we had set up about 4,22,000 pump sets for minor irrigation, and the figures has reached now 14,24,000. Then as far as private tubewells and filter points are concerned, the number was 49,000 up to 1960-61, and the number has reached now . . .

श्री राजनारायण : स्टेटवाईज पढ़ दिजिये।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I can give it but it will require some time.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : The hn. Member should give me notice and oshall be in a position to give.

श्री राजनारायण : जरूरी तो वही है। राजस्थान में कितने लगाये गये।

श्री राजनारायण : यह बजट स्पीच आप से रहे हैं। हम को यह बताइये कि राजस्थान में पम्पिग सेट कितने लगाये गये। कायदे की बात यहां होगी या बेकायदे की बात होगी।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Madam Deputy Chairman, I was mentioning the figure that 49,000 private tubewells and filter points were operating up *to* 1960-61. As against this, up to 1967-68 1,94,000 tubewells and filter points have been completed. Then up to 1960-61 there were 10,000 State tubewells, and the number has now reached 14,000 tubewells. So progressively the area which is being brought under minor irrigation has been increasing and by 1967-68 an additional area of 1,30,00,000 hectares would benefit from minor irrigation works. So these major irrigation works, soil conservation and afforestation programmes and these minor irrigation works go to show that large areas, which are subject to recurrent droughts, are being provided relief as a result of the measures taken by the Government of India and the State Governments.

Then a point has been made out about the Central team's recommendation in regard to the assistance to be given to the Rajasthan Government. On a previous occasion I had mentioned the figure, that about Rs. 9 crores has been recommended by the Central team as assistance to the Rajasthan Government. Now a fear is being expressed; the hon. Member, Mr. Mirdha, said that Rs. one crore has been made available and we do not know what is going to happen to the balance. Now there is a very well laid procedure for this. There should not be any fear on this whether the amounts would be advanced to the Rajasthan Government in time or not because, as soon as the Rajasthan Government reports that a particular amount has been spent under a particular head, the amounts are advanced, and up to Rs. 9 crores there could be no difficulty whatsoever, and the availability of that amount to the Rajasthan Government would be just depending on the reports of spending submitted by the Rajasthan Government. Then in regard to this I have also mentioned—and I wish again to repeat it—that this is subject to review in February; that means, in February there would be a review again, and if the Rajasthan Government is in a position to spend more, and if the Rajasthan Government's I requirements are found to be *more* than ' this, the Centre would be prepared to I advance substantially more amounts to [1] the Rajasthan Government. But to my

[Shri Annasaheb Shindc]

mind, to spend Rs. 9 crores in two months or three months is not an easy job ; it is quite a difficult job, but I wish the Rajasthan Government succeeds in implementing all the programmes they have taken up so that they are in a position to spend this amount and ask for more from the Centre.

Then take the point of tubewells which has been raised again and again on the floor of this House. For instance, the Centre's team has suggested that Rs. 85 lakhs may be made available to the Rajasthan Government immdiately for constructing sixty tubewells. Now, here again I wish to submit that the limitation is not that of the Centre or of funds. While discussing with the Rajasthan Government the Central Team found that the Rajasthan Government thought that they may not be in a position to complete more than 60 tubewells before June, 1969. We have assured them that if they want to dig forty more tubewells we shall be prepared to advance more funds to them. Again, only a few days earlier, I think yesterday or the day before yesterday, myMinistry has taken a decision to construct ten more tubewells in the Bikaner area, so that in the area which is rich in cattle wealth, water facilities are made available to the cattle for drinking purposes, and that good tubewells in the area are located wherefrom water for irrigation is also made available. Therefore, the point I am making out is that funds will not be a limiting factor. Now, we have had so much experience. The Government of India and the State Governments have had so much experience in providing relief under difficult conditions, I feel that we shall be in a position to tackle the situation very satisfactorily in times to come.

6 P. M.

श्री राजनारायण : शिन्दे साहब, राजस्थान की सरकार क्यों नहीं बनवा सकी उतने ट्यूब-वेल ? कोई कारण बताया है ?

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Some hon. Members went to the extent of saying that we should intervene and we should take up some of the relief measures in the hands of the Central Government. I wish to make this point very clear. Drought relief is constitutionally a subject matter falling within the purview of the State Government. It is the res-onsibility of the State Government. Even according to the reading of the Central Team the State Government is taking all the measures and steps required to meet the situation and I do not think the Centre can adopt a different yardstick in the case of Rajasthan. Even where there were non-Congress Ministries in many States, even when many of the constitutent units of the ruling party or the United Front were quarrelling amongst themeselves, the Centre did not think of intervening as far as drought relief in those States was concerned. I do not think this is a suggestion which is acceptable to us.

Then, I can quite understand and appreciate the concern expressed by hon. Members in regard to the piotection of cattle wealth. As has been expressed by Dr. Mangladevi Talwar, large sections of the population in western Rajasthan depend for their maintenance on the income from cattle. As a very distressing situation has developed in that part, naturally all of us are concerned about it. May I tell the hon. House that even before the Rajasthan Government reported anything to us, I myself personally took the initiative and sent a team of animal husbandry experts to Rajasthan and their first report was made available to us much before the Rajasthan Government formally approached us or the issue was raised ? So, we are very much alive to all these problems and for protecting the cattle wealth all necessary steps are being taken. Even then I must admit that some distress has developed. Naturally that has affected some of the cattle in Jaisalmer district, Barmer district, Bikaner area, etc. Some figures have been quoted by the hon. Member there to show that very large numbers of cattle have died. I have tried to ascertain the position. Of course, I do not say that no cattle has died, but the reports which are with the Rajasthan Government go to show that the percentage of mortality has gone up. Even normally 4 to 5 per cent mortality is there, but as a result of the distress, the mortality rate appears to have increased by 4 to 5 per cent more. So, the first priority was given to providing fodder in these drought-affected areas. Constant movement is taking place, both on Government account and private account, from outside areas, from the adjoining States to Rajasthan and at the subsidised rate of Rs. 8 per quintal the fodder is being made available.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Now it is Rs. 11.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : i This is the information with me. I will try to corroborate it. I shall check up the exact position. *(Interruption.)* Then, concessional rates for fodder have been sanctioned by the Railways and the reduction is in the neighbourhood of 76 per cent on 100 Kilometers distance to 47 per cent on 1,000 Kilometers distance. The concession for transport of cattle is 20 per cent. 'Busa' is being procured in the adjoining States of Madhya Pradesh, Punjab, U. P., etc. About 2,40,000 cattle have already migrated from these districts to the eastern parts of Rajasthan and also to the adjoining States. Now, migration is a normal thing, because Rajasthan area is such that even in normal periods some migration takes place. Now, in a much accentuated form migration is taking place. In order to protect the cattle, cattle-owners are taking their cattle from Rajasthan to some parts of Madhya Pradesh, Punjab, Har-yana, etc. Reports go to show that large numbers of cattle have migrated to the Udaipur division of Rajasthan from the western region.

Some hon. Members raised a fear tha this acute situation or difficult situation may give rise to some diseases, etc. I think it is a very good suggestion . . .

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: It is a fear.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : It is all right. It is a fear being expressed by hon. Members and it is a suggestion arising out of it that we should take necessary measures to see that epidemics do not develop and do not endanger our cattle life or human beings there. This is already engaging our attention. We shall take necessary steps and we shall see that the State Government takes necessary action to protect the cattle wealth. In order to prevent epidemics, whatever Central assistance is required will be given . . .

SHRI CHANDRA SHEKHAR : May I interrupt the hon. Minister ? Will you please be surprised to know that in the whole districts of Barmer and Jaisalmer, for the last twenty years there is not one lady doctor ? In the districts of Barmer and Jaisalmer, for the last twenty years, not a single lady doctor has been appointed. Ladies do not catch diseases in these two districts and the hon. Minister says that all precautions are being taken. It is good to rely upon such reports from the officers there, but not a single lady doctor is there in the whole of these two districts for the last twenty years.

श्री राजनारायण : चन्द्र शेखर जी, यह तो स्वास्थ्य विभाग से पूछिये, यह तो कृषि विभाग है ।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I was making the point that we will draw the attention of the State Government to this and whatever Central assistance is required to prevent epidemics we will be glad to extend to the State Government.

Then, Madam Deputy Chairman, in order to provide permanent relief in the western parts of Rajasthan the main solution is the sinking of tubewells. The Rajasthan Government is preparing a plan for sinking 500 tubewells in some parts of western Rajasthan. As soon as they finalise their programme, it will receive due consideration from the Government of India.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Would the hon. Minister kindly enlighten as to why the exploratory tubewells organisation was withdrawn, even before it had completed the stipulated number of tubewells, from Rajasthan and sent back ?

श्री राजनारायण : यह तो सिंचाई विभाग के लिये है ।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : May I explain ? Many of the hon. Members from Rajasthan have been raising this point from time to time. Now the exploratory tubewells organisation is not to sink tubewells in the State. It is the work of the State Government. The exploratory tubewells organisation, as the very word indicates, has to explore I the water potential in different areas. Actually the sinking of tubewells is the function of the State Government. The State Government has to set up a ground water organisation to take up the work of sinking tubewells. But in the case of Rajasthan we went out of our way. Work which is not normally carried out by the exploratory tubewells organisation was carried out in Rajasthan. They sank about 200 tubewells taking into consideration the difficulties of the area and the difficulties of the Rajasthan Govern, ment. But now the Rajasthan Govern, ment itself has a ground water organisa. tion. We are supposed to manufactur$_e$

[Shri Annasaheb Shinde]

some types of rigs in the country. I wish to submit that if the Rajasthan Government want any special types of rigs, which are not available in the country or manufactured in the country and if some foreign exchange is required, we shall be prepared to support the Rajasthan Government. We shall be prepared to sanction the necessary foreign exhange for such rigs. So that with the strengthened organisation the Rajasthan Government should be in a position to sink more and more tubewells.

Madam Deputy Chairman, I do not want to take much of your time, but I wish to mention that substantial help is being rendered by the Centre in order to overcome the difficult situation arising out of cyclone, drought, etc. As far as the current year is concerned the Central Team which has so far visited Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Mys< re, j Orissa, Rajasthan, etc., has recommended a total Central assistance to the tune of Rs. 82.61 crores, and out of that Rs. 46.88 crores has been actually advanced to the various State Governments.

In the end I wish to submit for the information of the hon. Members, whether the drought situation is in Andhra Pradesh, ! whether it is in Orissa, whether it is I cyclone situation in Bengal, it is engaging I the Government *ot* India's attention, and financial resources will not come in [the way of providing adequate relief to those areas. This is the only thing I | wanted to submit. I am again thankful ' to the hon. Members for the contributions they have made. If the proper atmos- 1 phere is maintained, I think we shall be 1 in a position to meet the difficult situation | arising out of these natural calamities. [

श्री कुम्भाराम आर्य : अध्यक्ष महोदया, वहां जो 1 रु० 12 आने की मजदूरी थी उसको जब अग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब वहां गये तो 1 रु० 50 पैसे कर के चले आये । इसकी क्या वजह है ?

SHRI SITARAM JAIPURIA : I would ask the hon. Minister : if any voluntary organisations have offered to sell foodgrains at a further subsidised rate, will the Government consider giving it to recognised institutions ? I raised that point. The Minister will be able to answer that.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I have not been able to follow.

SHRI SITARAM JAIPURIA : My question is : if any voluntary organisation is prepared to sell and distribute food-grains at a further subsidised rate than what Government is subsidising, will the Government be willing and prepared to take such assistance of voluntary organisations to sell foodgrains in the drought-affected areas, under the supervision of Government ?

SHRI ANNASAHEB SHINDE Normally, Madam, the food is distributed through Government agencies, but on merit if an organisation of repute is willing, it can be considered on merit.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Two amendments are there. No more.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We cannot go on like this. What do you want, Mrs. Talwar ?

श्री कुम्भाराम आर्य : उपसभापति महोदया मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री महोदय को चुप नहीं रहने दूंगा । 1 रु० 12 आने से वह 1 रु० 50 पैसे मजदूरी कर आये तो वह कैसे कर आये ।

श्री चन्द्रशेखर : 1 रु० 4 आने से 1 रु० 50 पैसे कर आये हैं ।

श्री कुम्भाराम आर्य : 1 रु० 12 आने से 1 रु० 50 पैसे किया है । मेरे पास राजस्थान सरकार की रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार का मंत्री आया और उसके बाद हमने 1 रु० 12 आने से 1 रु० 8 आने मजदूरी किया है । मैं इसका जवाब चाहता हूं ।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Madam Deputy Chairman, gratuitous relief to the weaker sections and physically incapacitated people is one of the items which comes under drought relief and Central assistance is naturally available to the Rajas than Government. Moreover one of the organisations, which is known as CARE, has agreed to organise feeding programmes in certain areas for children, expectant mothers, etc.

श्री राजनारायण : श्री सीताराम जैपुरिया साहब कह रहे हैं कि 10 परसेंट सबसिडी यह खुद करेंगे तो क्या इसको गवर्नमेंट सीताराम जी को देने को तैयार है जब कि 10 फीसदी वह देंगे ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am putting the amendments of Mr. Banka Behary Das. The question is :

2. "That at the end of the Motion, the following be added namely :—

"and having considered the same, this House is of opinion that (i) the Central Government should render full assistance for relief and rehabilitation of the people affected according to reasonable demands of the States; (ii) the Central Government should immediately set up a cell in the department concerned or the Planning Commission to evolve a programme of utilisation of all water potential, both surface and underground, to fight drought and augment production; (iii) the draft of the Fourth Five Year Plan should be revised accordingly to give priority to utilisation of water potential to the maximum extent; and (iv) the Government of India should set up an all-India fund for relief and rehabilitation of people affected by flood and drought or any other natural calamity.' "

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

3. "That at the end of the Motion the following be added, namely :—

'and having considered the same, this House regrets that the statement of the Minister on 'drought conditions prevailing in parts of the country', laid on the Table of the Rajya Sabha on November 18, 1968, does not mention anything about starvation deaths of Rajasthan nor about deaths of thousands of cattle which are emaciated due to want of fodder or drinking water.'"

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at fifteen minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 4th December, 1968.